सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 172, नई दिल्ली । रविवार, 01 सितम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जीवन साइकिल की सवारी करने जैसा है, संतुलन बनाये रखने के लिए चलते रहना जरूरी है।

03 आईएएस धर्मेंद्र को मिली दल्लि के नए चीफ सेक्रेटरी की कमान !,
06 वायनाड त्रासदी में छुपा सच
08 "मौन की चीख़: भारत में बलात्कार के संकट का खुलासा

डीटीसी जल्द नांगलोई डिपो से शुरू करेगी इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन, वेस्ट दिल्ली के लोगों को मिलेगी सहूलियतें

संजय बाटला

डीटीसी जल्द नांगलोई डिपो से इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू करेगी। डीटीसी प्रबंधन ने कहा है कि नांगलोई डिपो विद्युतीकरण बस संचालन की सूची में सम्मिलित है। इसलिए इस डिपो को विद्युतीकरण बस संचालन में तब्दील करने के कारण नांगलोई डिपो की सभी सीएनजी बसों को दिल्ली परिवहन निगम के दूसरे संबंधित सीएनजी संचालित डिपो में 31 अगस्त से स्थानांतरित किया जा रहा है।

नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) का इलेक्ट्रिक बसों के लिए डिपो तैयार करने का क्रम जारी है। इसी क्रम में अब नांगलोई डिपो को इलेक्ट्रिक बसों के लिए तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

डीटीसी प्रबंधन ने कहा है कि नांगलोई डिपो विद्युतीकरण बस संचालन की सूची में सम्मिलित है। इसलिए इस डिपो को विद्युतीकरण बस संचालन में तब्दील करने के कारण नांगलोई डिपो की सभी सीएनजी बसों को दिल्ली परिवहन निगम के दूसरे संबंधित सीएनजी संचालित डिपो में 31 अगस्त से स्थानांतरित किया जा रहा है। इससे भविष्य में ई-बसों के संचालन के लिए नागलोई डिपो को बिना किसी रुकावट के तैयार किया जा सके। डीटीसी ने कहा है कि बहुत जल्द नांगलोई डिपो से इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा।

दिल्ली मेट्रो के दावे नहीं बदल पाए हकीकत में, इस व्यस्ततम कॉरिडोर पर अगस्त में कम चली ट्रेनें

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने अगस्त 2018 की तुलना में इस वर्ष अगस्त के कार्यदिवस में 20 प्रतिशत अधिक ट्रेनें चलाने का दावा किया है। लेकिन डीएमआरसी ने माना है कि रेड लाइन पर ट्रेन की संख्या कम रही है लेकिन कोच अधिक इस्तेमाल किए गए। डीएमआरसी का कहना है कि 26 प्रतिशत कोच भी बढ़े हैं जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाई गई हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने अगस्त 2018 की तुलना में इस वर्ष अगस्त के कार्यदिवस में 20 प्रतिशत अधिक ट्रेनें चलाने का दावा किया है। लेकिन डीएमआरसी ने माना है कि रेड लाइन पर ट्रेन की संख्या कम रही है, लेकिन कोच अधिक इस्तेमाल किए गए। डीएमआरसी का कहना है कि 26 प्रतिशत कोच भी बढ़े हैं।

किसी कॉरिडोर पर ट्रेनों की संख्या परिचालन व रखरखाव की जरूरतों के अलावा कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है। इसमें त्योहार, व्यापार मेला, कार्यदिवस, सप्ताहांत व यात्रियों के दबाव इत्यादि शामिल है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाई गई हैं। मेट्रो के नेटवर्क में 336 ट्रेनें (2326 कोच हैं), जो वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

अगस्त के कार्यदिवस में ट्रेनों का परिचालन

रेड लाइन: आठ कोच की 32 ट्रेनें (कुल 256 कोच)

ब्लू लाइन: आठ कोच की 66 ट्रेनें (कुल 528 कोच)

पिंक लाइन: छह कोच की 44 ट्रेनें (कुल 264 कोच)

वायलेट लाइन: छह कोच की 40 ट्रेनें (240 कोच)

इन चार कॉरिडोर पर कुल ट्रेनें: 182 ट्रेनें/1288 कोच

कश्मीरी गेट ISBT में बसों के लिए 'टर्न अराउंड' समय घटकर होगा 30 मिनट, जाम से मिलेगी मुक्ति; एलजी ने दिए निर्देश

कश्मीरी गेट ISBT में बसों के लिए टर्न अराउंड समय घटकर 30 मिनट होने से जाम से निजात मिलेगी। उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने इसको लेकर निर्देश दिए हैं। वर्तमान में अंतरराज्यीय बसों के लिए न्यूनतम टर्न अराउंड (ठहराव) समय 45-60 मिनट है जिस कारण बसें आइएसबीटी के बाहर आसपास की सड़कों पर रुक जाती हैं जिसके चलते ट्रैफिक जाम हो जाता है।

नई दिल्ली। उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने शनिवार को आइएसबीटी कश्मीरी गेट का दौरा किया और यात्रियों को मिल रही सुविधाओं के साथ बस टर्मिनल से स्थानीय और अंतरराज्यीय बसों के संचालन का जायजा लिया। एलजी ने टर्मिनल का पूरी तरह से कायाकल्प करने के निर्देश दिए। एलजी का इस समय लोगों की यातायात संबंधी समस्याओं पर फोकस है। वह पिछले एक महीने से लगातार दिल्ली में यातायात की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं।

बस अड्डे पर एलजी ने पाया कि टर्मिनल के अंदर बस-बे से अंतरराज्यीय बसों के आने-जाने में अनावश्यक रूप से हो रही देरी के कारण आइएसबीटी के बाहर भारी जाम की स्थिति बनी हुई थी। एलजी को बताया गया कि वर्तमान में अंतरराज्यीय बस के लिए न्यूनतम टर्न अराउंड (ठहराव) समय 45-60 मिनट है, जिस कारण बसें आइएसबीटी के बाहर आसपास की सड़कों पर रुक जाती हैं, जिसके चलते ट्रैफिक जाम हो जाता है।

यमुना एक्सप्रेस-वे से फिल्म सिटी के लिए सीधी कनेक्टिविटी, 'स्लिप रोड' के निर्माण से आवाजाही होगी सुगम

यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 21 में बनने वाली फिल्म सिटी को यमुना एक्सप्रेसवे से सीधे जोड़ा जाएगा। इसके लिए प्राधिकरण स्लिप रोड का निर्माण करेगा। इससे फिल्म सिटी तक आवाजाही आसान होगी और यातायात भी सुगम होगा। फिल्म सिटी में फिल्म निर्माण के साथ-साथ इंस्टिट्यूट स्टूडियो आउटडोर लोकेशन मॉल आदि सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। निर्माण की जिम्मेदारी यमुना प्राधिकरण ने बेव्यू प्रोजेक्ट और भूटानी समूह को सौंपी है।

ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 21 के फिल्म सिटी के लिए यमुना एक्सप्रेसवे से सीधे कनेक्टिविटी दी जाएगी। इसके लिए यमुना प्राधिकरण स्लिप रोड का निर्माण करेगा। प्राधिकरण स्लिप रोड के लिए जल्द ही निविदा प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। स्लिप रोड के जरिए फिल्म सिटी जाने वाले लोगों के अलावा वाहनों की आवाजाही भी सुगम हो जाएगी।

यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 21 में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। इसके निर्माण की जिम्मेदारी यमुना प्राधिकरण ने बेव्यू प्रोजेक्ट और भूटानी समूह को सौंपी है। फिल्म सिटी का पहला चरण 230 एकड़ में होगा। इसमें फिल्म निर्माण से साथ-साथ, इंस्टिट्यूट स्टूडियो, आउटडोर लोकेशन, मॉल आदि अन्य सुविधाएं विकसित की जाएगी।

साइबरशाला: साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान

डॉ. अंकुर शरण

साइबरशाला एक महत्वपूर्ण पहल है जो सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग और ज्ञान की कमी से उत्पन्न हो रहे साइबर मुद्दों पर जागरूकता और शिक्षा प्रदान करती है। आज के डिजिटल युग में, लोगों की सुरक्षा के लिए साइबरशाला का उद्देश्य है कि वे साइबर अपराधों से बचाव के तरीकों को समझें और इन खतरों से सुरक्षित रहें। इस अभियान के माध्यम से, लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा और उन्हें ऑनलाइन सुरक्षा के महत्वपूर्ण उपायों के बारे में शिक्षित किया जाएगा।

एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: डॉ. वैभव सरन, फॉरेंसिक और साइबर एक्सपर्ट से बातचीत

साइबरशाला: नमस्कार डॉ. वैभव सरन, साइबरशाला में आपका स्वागत है। आज के दौर में साइबर अपराधों, खासकर सोशल मीडिया हैकिंग के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आप इस विषय पर अपनी विशेषज्ञ राय दें।

डॉ. वैभव सरन: धन्यवाद। यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया हैकिंग के मामले तेजी से बढ़े हैं। अधिकतर लोग आजकल सोशल मीडिया का उपयोग व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह से कर रहे हैं, जिससे उनकी संवेदनशील जानकारी ऑनलाइन हो जाती है। हैकर्स इस स्थिति का फायदा उठाते हैं और कमजोरियों का शिकार बनाते हैं।

साइबरशाला: क्या आप हमें बता सकते हैं कि सोशल मीडिया हैकिंग के सबसे सामान्य तरीके कौन से हैं?

डॉ. वैभव सरन: जी हां, सोशल मीडिया हैकिंग के कई सामान्य तरीके हैं। इनमें से सबसे प्रमुख हैं फ़िशिंग (Phishing), जिसमें हैकर्स फर्जी वेबसाइट्स या ईमेल्स के जरिए यूजर्स की लॉगिन जानकारी चुराते हैं। दूसरा तरीका है पासवर्ड गेसिंग, जिसमें कमजोर पासवर्ड्स का अनुमान लगाकर अकाउंट्स को एक्सेस किया जाता है। इसके अलावा, मालवेयर (Malware) और कीलॉगर (Keylogger) जैसे खतरनाक सॉफ्टवेयर्स भी उपयोग किए जाते हैं।

साइबरशाला: इनसे बचने के लिए क्या एहतियात बरतने चाहिए?

डॉ. वैभव सरन: सबसे पहले, हमेशा मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें और उसे नियमित रूप से बदलते रहें। आपके पासवर्ड में बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, संख्या, और विशेष चिन्हों का मिश्रण होना चाहिए। दूसरा, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) को सक्रिय करें, जिससे

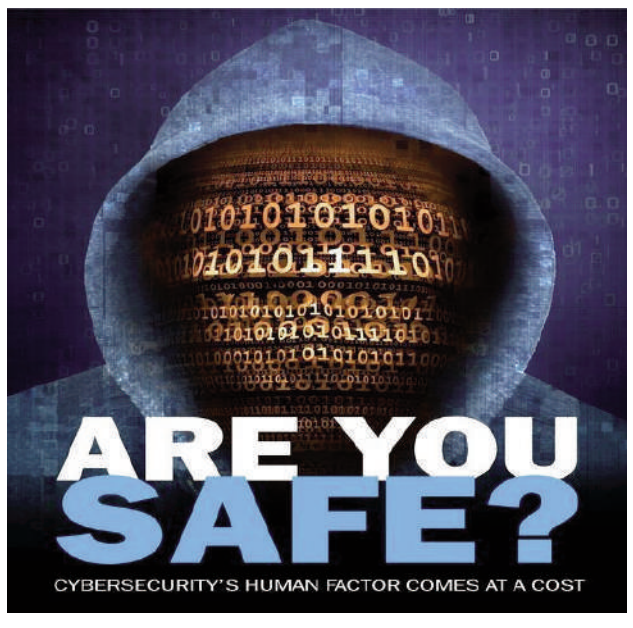

अगर कोई व्यक्ति आपका पासवर्ड जान भी जाए, तो वह आपके अकाउंट में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसके अलावा, कभी भी अनजान या संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और फ़िशिंग के प्रति सतर्क रहें।

साइबरशाला: अगर किसी का सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाता है, तो उसे क्या करना चाहिए?

डॉ. वैभव सरन: अगर किसी का अकाउंट हैक हो जाता है, तो सबसे पहले उसे अपने पासवर्ड को तुरंत बदलना चाहिए। अगर पासवर्ड बदलने का विकल्प नहीं मिल रहा है, तो अकाउंट को रिकवर करने के लिए संबंधित प्लेटफार्म की रिकवरी प्रक्रिया का पालन करें। साथ ही, हैकिंग की घटना की सूचना प्लेटफार्म के सपोर्ट टीम को दें और स्थानीय पुलिस या साइबर क्राइम सेल को रिपोर्ट करें।

साइबरशाला: आपके अनुसार, लोगों को सोशल मीडिया के उपयोग के दौरान कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए?

डॉ. वैभव सरन: सोशल मीडिया का उपयोग करते समय, व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक करने से बचें। अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को अपडेट रखें और यह सुनिश्चित करें कि आपकी जानकारी केवल उन्हीं लोगों को दिखाई दे, जिन पर आप भरोसा करते हैं। इसके अलावा, अजनबियों से मिलने वाले फ्रेंड रिक्वेस्ट को सावधानीपूर्वक स्वीकार करें और हमेशा सतर्क रहें।

साइबरशाला: डॉ. सरन, साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी है, वह हमारे पाठकों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी।

डॉ. वैभव सरन: धन्यवाद। साइबर सुरक्षा आज के डिजिटल युग में अत्यंत महत्वपूर्ण है, और मुझे खुशी है कि साइबरशाला जैसे प्लेटफार्म इस दिशा में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि लोग इन सुझावों का पालन करेंगे और अपने ऑनलाइन जीवन को सुरक्षित बनाए रखेंगे।

2 सितंबर को शिव और सिद्ध योग में मनाई जायेगी सोमवती अमावस्या

ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का बेहद महत्व है। इस दिन व्रत, पूजन और पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व है। महिलाएं सोमवती अमावस्या के दिन पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं।

सोमवार 2 सितंबर को भाद्रपद मास की अमावस्या है। सोमवार को अमावस्या होने से इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि सोमवती अमावस्या की तिथि पर पितरों का तर्पण करना बहुत शुभ होता है। इस दिन पितरों को तर्पण करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि पंचांग के अनुसार भाद्रपद अमावस्या तिथि 2 सितंबर 2024 को सुबह 05:21 मिनट पर शुरू होगी। वहीं, इसका समापन 3 सितंबर को सुबह 07:24 मिनट पर होगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार, अमावस्या में स्नान और दान उदयातिथि में मान्य होता है। इसलिए भाद्रपद अमावस्या 2 सितंबर को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि जब सोमवार के दिन आती है। तब इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह सूर्योदय से लेकर शाम के 6:20 मिनट तक शिव योग रहेगा। इसके बाद सिद्ध योग रहेगा। ऐसे में अगर आप विधि-विधान पूर्वक भगवान शिव की पूजा सोमवती अमावस्या के दिन करते हैं तो पारिवारिक जीवन में आपको सुखद बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस योग में शिव जी की साधना करने से अक्षय फलों की प्राप्ति भक्तों को होती है। इसके साथ ही भगवान शिव के मंत्रों का जप करना भी आपके लिए हितकारी रहेगा, इससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी और साथ ही आपके बिगड़ते काम भी बनने लगेंगे।

ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का बेहद महत्व है। इस दिन व्रत, पूजन और पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व है। महिलाएं सोमवती अमावस्या के दिन पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। पितृ दोष निवारण के लिए दिन अत्यंत शुभ माना गया है। इस अमावस्या पर किए गए दान-पुण्य और तीर्थ स्नान से अक्षय पुण्य मिलता है। मन शांत होता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। इस तिथि पर अपने-अपने क्षेत्रों की पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए और क्षेत्र के पौराणिक महत्व वाले तीर्थों के, मंदिरों के दर्शन करना चाहिए। पूजा-पाठ आदि शुभ काम करना चाहिए।

ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि अगर हम किसी नदी में स्नान करने नहीं जा पाते हैं तो घर पर पानी में गंगाजल मिलाएं और तीर्थों का ध्यान करते हुए स्नान करें। सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। इसके लिए तांबे के लोटे में जल भरें और सूर्यदेव को चढ़ाएं। ऐसा करने से भी तीर्थ और नदी स्नान के बराबर पुण्य मिल सकता है। स्नान के बाद जरूरतमंद लोगों को अनाज और गोशाला में धन, हरी घास का दान करें। अमावस्या पर पितरों के लिए धूप-ध्यान करें। घर में दोपहर करीब 12 बजे गाय के गोबर से बने कंडे जलाएं और उसके अंगारों पर गुड़-घी डालें। पितरों का ध्यान करें। हथेली में जल लें और अंगूठे की ओर से पितरों को अर्घ्य अर्पित करें। किसी शिव मंदिर में दीपक जलाएं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ऊँ नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें।

सोमवती अमावस्या पर शिव योग

ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि शिव योग को ज्योतिष शास्त्र में बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। इस योग में भक्त अगर भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उन्हें मनचाहे फल प्राप्त होते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह सूर्योदय से लेकर शाम के 6:20 मिनट तक शिव योग रहेगा। इसके बाद सिद्ध योग रहेगा।

सोमवती अमावस्या तिथि

2 सितंबर 2024 को सुबह 05:21 मिनट पर शुरू

3 सितंबर को सुबह 07:24 मिनट पर समाप्त

गंगाजल से स्नान

भविष्यवक्ता डा. अनीष व्यास ने बताया कि इस दिन गंगाजी या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत पुण्यकारी माना गया है। स्नान का उत्तम समय सूर्योदय से पूर्व माना जाता है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या पर विधिवत स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। यदि आप नदियों में स्नान करने नहीं जा सकते तो आप घर में ही थोड़ा सा गंगाजल नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करें। मान्यता यह भी है कि इस दिन विधिवत स्नान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है।

अमावस्या का ज्योतिषीय महत्व

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि अमावस्या तिथि के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। जहां सूर्य आग्नेय तत्व को दर्शाता है तो वहीं चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। सूर्य के प्रभाव में आकर चंद्रमा का प्रभाव शून्य हो जाता है। इसलिए मन को एकाग्रचित करने का यह कारगर दिन होता है। इसलिए अमावस्या का दिन आध्यात्मिक चिंतन के लिए श्रेष्ठ होता है। अमावस्या को जन्म लेने वाले की कुंडली में चंद्र दोष होता है।

सूर्य को प्रदान करें अर्घ्य

कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि पदमपुराण के अनुसार पूजा, तपस्या, यज्ञ आदि से भी श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती, जितनी कि प्रातः स्नान कर जगत को प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से होती है। इसलिए पूर्व जन्म और इस जन्म के सभी पापों से मुक्ति और भगवान सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को नियमित सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ्य अवश्य प्रदान करना चाहिए।

पीपल के वृक्ष में पितरों का वास

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि माना जाता है कि अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है। इस दिन पीपल और भगवान विष्णु का पूजन किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस दिन मीठे जल में दूध मिलाकर चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन पीपल के पेड़ पर मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। पूजन के बाद पीपल की यथा शक्ति परिक्रमा करके जीवन में आने वाली सभी समस्याएं खत्म होने के लिए प्रार्थना करें।

दान करने से मिलेगा पुण्य

कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि इस दिन अन्न, दूध, फल, चावल, तिल और आवंले का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गरीबों, साधु, महात्मा तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। स्नान- दान आदि के अलावा इस दिन पितरों का तर्पण करने से परिवार पर पितरों की कृपा बनी रहती है।

पितरों को करें प्रसन्न

भविष्यवक्ता डा. अनीष व्यास ने बताया कि सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के नाम जल में तिल डालकर दक्षिण दिशा में तर्पण करें। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। ऐसे में इस दिन तर्पण करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और वे आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करें। दूध चढ़ाएं और सात बार परिक्रमा लगाएं। पीपल के नीचे दीपक जलाएं। ऐसा करने से परिवार में खुशहाली आती है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन पितरों के निमित्त गीता के सातवें अध्याय का पाठ करना चाहिए। पितरों का ध्यान करते हुए सोमवती अमावस्या के दिन दान करें। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल का एक पौधा लगाएं। ऐसा करने से पितर खुश होते हैं। वह आर्थिक स्थिति सुधरती है।

करें उपाय

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि अमावस्या के दिन तिल को आटे में मिलाकर रोटी बनाए और गाय को खिलाएं। इससे घर में सुख-शांति आएगी। अमावस्या के दिन स्नान के बाद आटे की गोलियां बनाएं। इस गोलियों को मछलियों को खिलाएं। इस उपाय से कई परेशानियां दूर होती हैं। अमावस्या के दिन पितरों का ध्यान करते हुए जरूरतमंद या गरीब को दान करें। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त गीता का सातवां अध्याय का पाठ करें। अमावस्या के दिन जल में तिल मिलाकर उसे दक्षिण दिशा की ओर तर्पण करें। ऐसा करने से पितर आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन दूध में अपनी छाया देखें। इस दूध को काले कुत्ते को पिलाएं। इससे मानसिक तनाव दूर होता है। अमावस्या के दिन शाम के समय ईशान कोण में दीपक जलाएं। बत्ती के लिए लाल रंग के धाते का इस्तेमाल करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अमावस्या के चीटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती है।

पांडवों की राजधानी - इंद्रप्रस्थ नगरी

इंद्रप्रस्थ महाभारत कालीन अतिप्राचीन नगरी है, जो पांडवों की राजधानी हुआ करती थी. महाभारत महाकाव्य में इस नगरी के निर्माण एवं विस्तार का विस्तृत उल्लेख है।

धृतराष्ट्र की सलाह पर युधिष्ठिर ने पार्थ श्रीकृष्ण के सहयोग से इंद्रप्रस्थ नगरी की स्थापना की थी, जिसके वास्तुकला की रचना भगवान विश्वकर्मा ने की थी।

सागर जैसी चौड़ी खाई से घिरा, स्वर्ग गगनचुम्बी चारदीवारी से घिरा एवं चंद्रमा या सूखे मेघों जैसा श्वेत यह नगर अद्भुत, अद्वितीय एवं अकल्पनीय लगता था।

भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र के अपने प्रति दर्शित नैतिक व्यवहार के परिणामस्वरूप पांडवों ने खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में परिवर्तित कर दिया था।

भव्य महलों, अट्टालिकाओं और स्थापत्य की उन्नत कला से सुसज्जित यह नगरी इंद्र की नगरी की भांति दिखती थी, इस कारण ही इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया था।

भारतीय संस्कृति और धार्मिकता में एक प्रमुख स्थान रखता है बरसाना

बरसाना, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित एक पौराणिक और धार्मिक स्थल है, जो विशेष रूप से देवी राधा के जन्मस्थान के रूप में प्रसिद्ध है। यह नगर भारतीय संस्कृति और धार्मिकता में एक प्रमुख स्थान रखता है और यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर, त्यौहार, और धार्मिक महत्व इसे एक अद्वितीय स्थल बनाते हैं।

बरसाना को राधा की जन्मभूमि के रूप में मान्यता प्राप्त है। देवी राधा, जो भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सहयोगी और प्रेमिका मानी जाती हैं, का जन्म यहीं हुआ था। राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानियाँ भारतीय पौराणिक कथाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और बरसाना इस प्रेम कहानी का केंद्र बिंदु है। यहाँ पर राधा के साथ जुड़ी कई धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएँ हैं जो इसे एक विशेष धार्मिक स्थल बनाती हैं।

प्रमुख स्थल और मंदिर

राधा रानी मंदिरः यह मंदिर बरसाना का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहाँ पर देवी राधा की पूजा की जाती है। यहाँ का भव्य मंदिर और उसकी ऐतिहासिक आर्किटेक्चर श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करती है।

बरसाना की पहाड़ियाँः यहाँ की पहाड़ियाँ भी धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। मान्यता के अनुसार, ये पहाड़ियाँ राधा और कृष्ण के मिलन की कहानियों से जुड़ी हुई हैं।

हाउस ऑफ राधा (राधा कुटीर): यह स्थल देवी राधा के निवास स्थान के रूप में माना जाता है। यहाँ पर राधा के जीवन की झलक देखने को मिलती है और इसे धार्मिक यात्रियों द्वारा अत्यंत पवित्र माना जाता है।

प्रमुख त्यौहार और सांस्कृतिक परंपराएँ

होलीः बरसाना की होली विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसे 'लठमार होली' के नाम से जाना जाता है, जिसमें महिलाएँ रंगीन लाठियों से पुरुषों पर रंग डालती हैं। यह त्यौहार यहाँ की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और इसमें भाग लेने के लिए देश-विदेश से लोग यहाँ आते हैं।

राधा जन्माष्टमीः राधा जन्माष्टमी पर यहाँ भव्य आयोजन होते हैं। इस दिन विशेष पूजा-अर्चना की जाती है और पूरे नगर को सजाया जाता है।

रासलीलाः बरसाना में आयोजित होने वाली रासलीला, राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानियों को दर्शाने वाले नाट्य प्रदर्शन हैं। यह धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भक्तों को आकर्षित करते हैं और यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को प्रकट करते हैं।

पर्यटन और यात्रा

बरसाना की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक होता है, जब मौसम सुहावना रहता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मथुरा एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है, और यहाँ से बरसाना तक सड़क मार्ग द्वारा आसानी से पहुँचा जा सकता है।

यात्रा के दौरान, स्थानीय हस्तशिल्प और परंपरागत भोजन का आनंद लेना न भूलें। यहाँ की रंगीन गलियाँ, बाजार, और विशेष रूप से होली के दौरान का माहौल एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं।

बरसाना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ के मंदिर, त्यौहार, और सांस्कृतिक परंपराएँ इस स्थान को एक विशेष और अद्वितीय अनुभव प्रदान करती हैं। राधा की जन्मभूमि होने के कारण, बरसाना भारतीय धार्मिकता और पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ की यात्रा एक दिव्य अनुभव प्रदान करती है और भारतीय संस्कृति की गहराइयों को समझने का अवसर देती है।

विवाह गुण मिलान/दांपत्य जीवन

विवाह जीवन का एक ऐसा निर्णय है जिसका सफल/असफल होना सीधे तरीके से जातक के जीवन को प्रभावित करता है, एक सफल वैवाहिक जीवन आपकी प्रगति की रफ्तार को बढ़ाता है और असफल वैवाहिक जीवन प्रगति की रफ्तार को भले ही ना घटाए मगर कुछ देर के लिए ही सही मंद जरूर कर देता है ऐसा मेरा मानना है, वो इसलिए भी क्योंकि हमारी संस्कृति पाश्चात्य देशों की तरह नहीं है हम भले ही अब संयुक्त परिवारों में ना रहते हों मगर कहीं ना कहीं हम अभी भी संयुक्त परिवारों से ही जुड़े हुए हैं।

विवाह से पहले अक्सर गुण मिलाए जाते हैं और 36 में से 18 या उससे ज्यादा होने पर विवाह के लिए उत्तम बताये जाते हैं और विवाह संपन्न करा दिया जाता है, लेकिन सिर्फ गुणों के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि वैवाहिक जीवन सफल होगा या नहीं।

उदाहरण के तौर पर अगर दोनों का मंगल/सूर्य उग्र है दोनों में से कोई हठी स्वभाव छोड़ने को तैयार नहीं है तो गुण मिलान के बावजूद समस्या आ सकती हैं जिसे आज की भाषा में 'इंगो क्लेसेश' कहते हैं।

एक दूसरे उदाहरण में अगर दोनों का चन्द्रमा कमजोर है या लग्न बलवान नहीं है तो ऐसी स्थिति में सम्भावना है कि ऐसे दम्पति किसी भी चीज को लेकर ठोस निर्णय ना ले सकें और कई बार जरूरत से ज्यादा खर्चा कर लें जिसको लेकर सम्भव है उन्हें बाद में पछतावा हो।

एक और प्रमुख बिंदु है जो मैंने काफी जन्मपत्रियों में देखा है अगर पंचमेश की स्थिति दोनों की कुंडली में कमजोर होती है तो संतान सुख में कमी का योग बनता है, जिस वजह से दम्पति के जीवन का एक बड़ा हिस्सा दुःख सहते हुए बीत सकता है, दूसरे देशों की तुलना में हमारे देश में ऐसा होना सम्भव भी लगता है क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग विवाह ही सिर्फ संतानोत्पत्ति की वजह से करते हैं।

कई बार देखा है की शुक्र- मंगल का योग सप्तम भाव में बन जाए या फिर किसी भी रूप से सप्तम भाव या सप्तमेश को प्रभावित करें तो ऐसी स्थिति में पति-पत्नी के दांपत्य जीवन में बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है।

गुण मिलने के बाद भी यदि सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश अपने से 8वां, 12वें भाव में बैठ जाए और अशुभ ग्रह की दृष्टि से प्रभावित हो जाए तो निश्चित मानिए पति-पत्नी की कलह है जीवन भर समाप्त नहीं होती, अतः ध्यान रहे- गुण मिलापक के साथ-साथ कुंडली अध्ययन भी जरूर करना चाहिए।

इस लेख को छापने का उद्देश्य पढ़ने वाले के मन में किसी तरह का डर बैठाना या संदेह डालना नहीं बल्कि जागरूक करना है। यह बात भी बिल्कुल सही है कि प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता लेकिन प्रारब्ध के अशुभ वेग को कुछ सावधानियां बरत कर कम किया जा सकता है।

भगवान कृष्ण ने क्यों तोड़कर फेंक दी थी अपनी प्रिय बांसुरी, जानिए क्या है कहानी

अनन्या मिश्रा

भगवान कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया, जब श्रीकृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी तो तोड़कर हमेशा के लिए फेंक दिया था। तो आइए जानते हैं श्रीकृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी को क्यों तोड़कर फेंक दिया था।

दुनियाभर में श्रीकृष्ण और राधा रानी के कई मंदिर हैं। श्रीकृष्ण और राधा रानी का प्रेम बेमिसाल था। जब भी श्रीकृष्ण की छवि सामने आती है, तो उनके हाथ में बांसुरी जरूर दिखती है। श्रीकृष्ण को बांसुरी अत्यंत प्रिय थी और जब भी वह बांसुरी बजाया करते थे, तो गोपियां सुधबुध भूलकर श्रीकृष्ण के पास खिंची चली आती थीं। न सिर्फ राधा रानी और गोपियां बल्कि हर कोई कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया, जब श्रीकृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी तो तोड़कर हमेशा के लिए फेंक दिया था। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी को क्यों तोड़कर फेंक दिया था।

जानिए क्या है कहानी

श्रीकृष्ण और राधा रानी का प्रेम दुनियाभर में फेमस है। आज भी श्रीकृष्ण से पहले राधा रानी का नाम लिया जाता है। आज भी राधा-कृष्ण के प्रेम की मिसाल दी जाती है। भले ही राधा-कृष्ण ने विवाह नहीं किया था, लेकिन दोनों के मन में एक-दूसरे के प्रति जो प्रेम और सम्मान था, वह अन्य किसी के लिए नहीं था और यह भाव ताउम्र रहा था। कहा जाता है कि श्रीकृष्ण सिर्फ देवी राधा के लिए बांसुरी बजाया करते थे, तो वहीं राधा रानी भी श्रीकृष्ण की बांसुरी सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाती थीं। जैसे ही कान्हा की बांसुरी की धुन राधा को सुनाई देती वह फौरन श्रीकृष्ण से मिलने पहुंच जाती थी।

राधा को छोड़कर मथुरा गए श्रीकृष्ण

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राधा रानी और श्रीकृष्ण एक-दूसरे के लिए बने थे और वह बचपन में साथ रहते थे। लेकिन समय के चक्र के साथ ही कृष्ण भगवान को अपने दायित्वों की पूर्ति के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। इस तरह से वह राधा रानी से दूर चले गए। लेकिन

श्रीकृष्ण को विदा करते हुए देवी राधा ने उनसे वचन लिया था कि जब उनका अंतिम समय आएगा, तो श्रीकृष्ण उन्हें दर्शन देंगे और बांसुरी बजाकर सुनाएंगे। श्रीकृष्ण ने वचन देते हुए इस बात को मान लिया। भले ही श्रीकृष्ण देवी राधा से दूर हो गए, लेकिन वह बांसुरी को हमेशा अपने साथ रखते थे।

श्रीकृष्ण ने क्यों तोड़ दी बांसुरी

वजन के अनुसार, जब देवी राधा का आखिरी समय आ गया, तो वह श्रीकृष्ण से मिलने द्वारका पहुंची। वहीं श्रीकृष्ण ने भी अपना वचन निभाते हुए राधा रानी से मुलाकात की। पृथ्वी लोक पर यह राधा-कृष्ण की अंतिम मुलाकात थी। वादे के मुताबिक राधा रानी को श्रीकृष्ण ने बांसुरी बजाकर सुनाई। बांसुरी की मधुर धुन को सुनकर राधा रानी ने श्रीकृष्ण के कंधे पर सिर रख लिया और अपने प्राण त्याग दिया। राधा की मृत्यु श्रीकृष्ण बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस विरह में उन्होंने अपनी बांसुरी को तोड़कर वहीं झाड़ियों में फेंक दिया। इसके बाद श्रीकृष्ण ने यह निश्चित किया कि अब वह फिर कभी बांसुरी नहीं बजाएंगे।

बारिश में आपका फोन नहीं होगा गीला, जानें कैसे?

मॉनसून सीजन अभी चल ही रहा है और बारिश में भीगना किसे पसंद नहीं होता है ! खासकर के जब उमश भरी गर्मी हो और बारिश की फुहार आपके ऊपर पड़ती है तो मन एकदम खिल उठता है। हालांकि गैजेट्स के जमाने में आपके जेब में या बैग के अंदर दो-तीन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रहना आम सी बात हो गई है और इसमें भी खास करके मोबाइल फोन।

आप भीगते हैं तो आनंद आता है लेकिन गलती से भी अगर आपका मोबाइल फोन पानी में भीग गया बारिश में भीग गया तो यह एक मुसीबत खड़ी होने वाली बात होती है, क्योंकि इन इलेक्ट्रिक डिवाइस की यही सबसे बड़ी कमी है कि पानी पड़ते ही या नमी के कारण यह जल्दी से खराब हो जाते हैं। तो आप जानना चाहते हैं कि अगर पानी में गिरने से या बारिश में जाने से आपका मोबाइल फोन कैसे सुरक्षित रख सकते हैं या अगर आपका मोबाइल फोन किसी कारण वश भीग भी गया है तो उसके बाद आपको क्या प्रिकॉशन अपनाना चाहिए ?

वॉटरप्रूफ मोबाइल कवर या केस का इस्तेमाल

मोबाइल में कवर का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं या अगर आप मोबाइल को किसी केस में रखते हैं तो ध्यान रखें की बरसात के मौसम में आप वाटरप्रूफ केस का इस्तेमाल करें क्योंकि आपात स्थिति आने में या अचानक से बारिश आने में आपके फोन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्योंकि इन वाटर प्रूफ केस में काफी हद तक आपका फोन सुरक्षित रहेगा और पानी से बचा रहेगा, हालांकि वाटरप्रूफ केस में रखने के बाद भी आपको यह सावधानी रखनी होगी कि आप अपने फोन को सीधे बारिश के संपर्क में ना रखें बल्कि वाटर प्रूफ केस में रखने के बाद भी उसे बैग या सुरक्षित जगह रख दें।

ज़िप लॉक बैक का करें इस्तेमाल

आप मार्केट में देखते होंगे की तरह-तरह के रंग-बिरंगे ज़िप लॉक बैगआपको आसानी से मिल जाते हैं खासकर मोबाइल रखने के हिसाब से भी आजकल मार्केट में ज़िप लॉक बैग आने लग गए हैं, तो ऐसे में मानसून सीजन में घर से बाहर निकलने से पहले आप अपने पास एक ज़िप लॉक जरूर रखें और जैसे ही बारिश की शुरुआत हो अपने फोन को ज़िप लॉक बैग में डालकर सुरक्षित कर लें और फिर अच्छे से बैग में इसको रख दें। इतना ही नहीं अगर आपके पास फोन के अलावा इयरबड्स और हेडफोन जैसे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी है तो उन्हें भी आप इस ज़िप लॉक बैग में रखकर सुरक्षित कर सकते हैं।

गणेश उत्सव को लेकर नन्हे बच्चों में भी है काफी उत्साह

नन्हे नन्हे बच्चों भी बना रहे हैं मिट्टी से श्री गणेश की प्रतिमा

सुषमा रानी

दिल्ली। गणेश चतुर्थी से 7 सितम्बर को श्री गणेश उत्सव प्रारम्भ हो रहा है तो संस्थाओं द्वारा एवं मंदिरों में तैयारियां की जा रही हैं। हर वर्ष नगर में जगह जगह गणेश उत्सव पंडाल भी सजते हैं। देवताओं में प्रथम आराध्य श्री गणेश के उत्सव को लेकर जगह जगह बच्चों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ बच्चे अपने अभिभावकों के साथ गणेश पूजन के लिए अभी से मूर्तियां पसंद कर रहे हैं तो कुछ बच्चे अपने घरों में श्री गणेश की प्रतिमा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साक्षी राय ने बताया कि वह अपने बेटे गुरसांज के लिए तालाब की चिकनी मिट्टी लेकर आई हैं। वह अपने बेटे के साथ भगवान श्री गणेश की छोटी से प्रतिमा बना रही हैं। इस प्रतिमा को सुखाकर बेटे से मूर्ति के सुंदर रंग करवाएंगी। इसी प्रकार मन्नत अरोड़ा ने भी बताया कि उसके बेटे जसमीत को श्री गणेश की मूर्ति बनाने का जनून है। वह मिट्टी और रंग लेकर आई हैं। रविवार को छुट्टी के दिन से मूर्ति बनाना शुरू करेंगी। दुकानदार सतपाल बठला ने बताया कि काफी बच्चे श्री गणेश की मूर्ति बनाने के लिए रंग व सामान लेने के लिए माता पिता के साथ आ रहे हैं। स्वामी पृथ्वी पुरी ने कहा कि आज के समय में बच्चों द्वारा मूर्ति बनाना एक अच्छा प्रयास है। इससे बच्चों के ज्ञान के विकास के साथ उनकी पर्सनैलिटी का विकास होता है। उन्होंने कहा कि श्री गणेश चतुर्थी से बच्चों मंदिरों में ले जाना चाहिए। बच्चों को दस दिनों में पूजा-अर्चना और प्रसाद का काम सौंपा जा सकता है। बच्चों से कहा जा सकता है कि वे नई-नई आरतियां और भजन याद करें। उन्होंने कहा कि बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है। बच्चों को मिट्टी से श्री गणेश जी की प्रतिमाएं बनाने का हुनर सिखाया जा सकता है। बच्चों से कहा जा सकता है कि वे खुद से बनाई गई मिट्टी की श्री गणेश की प्रतिमाएं घरों में स्थापित करें।

आईएएस धर्मेंद्र को मिली दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी की कमान!, नाम का ऐलान

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दल्लि के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार का कार्यकाल 31 अगस्त को खत्म होने जा रहा है. नए मुख्य सचिव के तौर पर एजीएमयूटी कैडर के 1989 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र का नाम फाइनल. दल्लि के नए सीएस के रूप में धर्मेंद्र की नियुक्ति संबंधी आदेश जारी. आईएएस धर्मेंद्र वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिवp हैं. जन्हिोंने यह जम्मिेदारी 19 अप्रैल 2022 को संभाली थी. नरेश कुमार को दल्लि का मुख्य सचिव बनाए जाने के वक्त भी उनका नाम 2022 में काफी जोरशोर से चर्चाओं में रहा था. दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव धर्मेंद्र बीटेक (सिविल इंजीनियर) हैं और उनका 7 महीने का कार्यकाल प्रशासनिक सेवा मे बचा है। अरुणाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी बनाए जाने से पहले वह नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के भी काफी समय तक चेयरपर्सन रहे हैं. इसके बाद उनको गृह मंत्रालय के आदेशों पर अप्रैल 2022 में अरुणाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी की जम्मिेदारी दी गई. आईएएस धर्मेंद्र दिल्ली सरकार के तमाम विभागों में खास जिम्मेदारियां पहले भी निभा चुके हैं. वह दिल्ली सरकार के रेवेन्यू विभाग में बतौर डिविजनल कमिश्नर सह सचिव के अलावा अर्बन डेवलपमेंट, दिल्ली नगर निगम आदि में अलग-अलग जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. इस दौरान वह केंद्र सरकार के भी अलग-अलग मंत्रालय/विभागों में बतौर जॉइंट सेक्रेटरी आदि के रूप में कार्यभार संभाल चुके हैं.

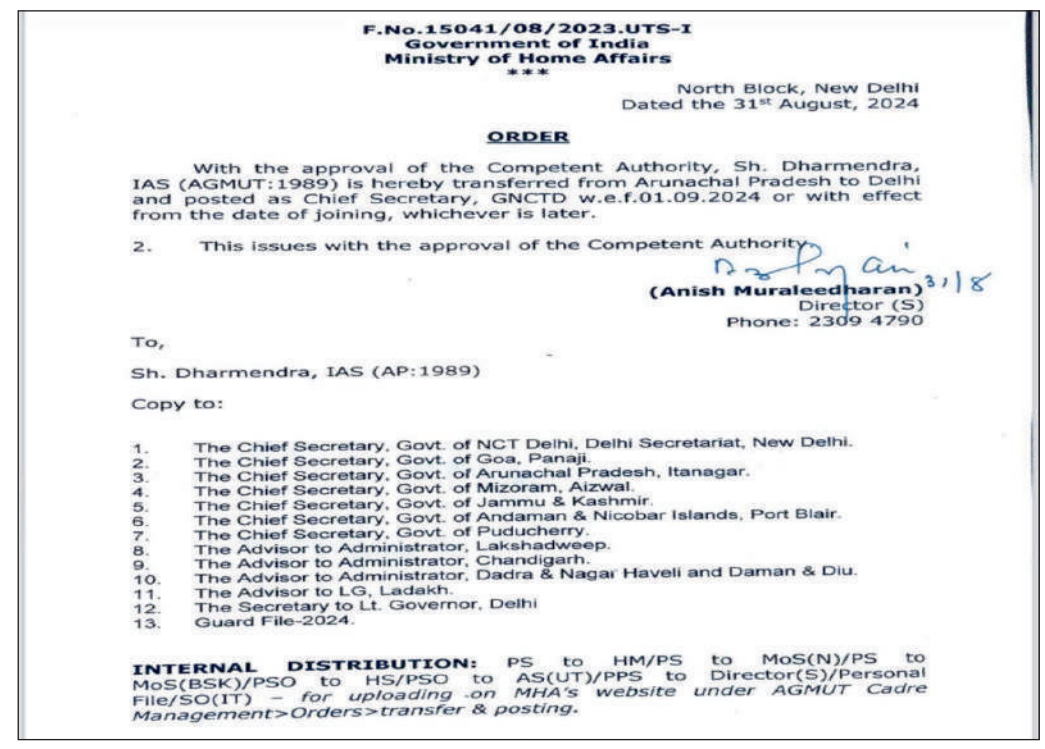

F.No.15041/08/2023.UTS-I
Government of India
Ministry of Home Affairs
***

North Block, New Delhi
Dated the 31st August, 2024

ORDER

With the approval of the Competent Authority, Sh. Dharmendra, IAS (AGMUT:1989) is hereby transferred from Arunachal Pradesh to Delhi and posted as Chief Secretary, GNCTD w.e.f.01.09.2024 or with effect from the date of joining, whichever is later.

2. This issues with the approval of the Competent Authority.

(Anish Muraleedharan) 31/8
Director (S)
Phone: 2309 4790

To,

Sh. Dharmendra, IAS (AP:1989)

Copy to:

1. The Chief Secretary, Govt. of NCT Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
2. The Chief Secretary, Govt. of Goa, Panaji.
3. The Chief Secretary, Govt. of Arunachal Pradesh, Itanagar.
4. The Chief Secretary, Govt. of Mizoram, Aizwal.
5. The Chief Secretary, Govt. of Jammu & Kashmir.
6. The Chief Secretary, Govt. of Andaman & Nicobar Islands, Port Blair.
7. The Chief Secretary, Govt. of Puducherry.
8. The Advisor to Administrator, Lakshadweep.
9. The Advisor to Administrator, Chandigarh.
10. The Advisor to Administrator, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu.
11. The Advisor to LG, Ladakh.
12. The Secretary to Lt. Governor, Delhi
13. Guard File-2024.

INTERNAL DISTRIBUTION: PS to HM/PS to MoS(N)/PS to MoS(BSK)/PSO to HS/PSO to AS(UT)/PPS to Director(S)/Personal File/SO(IT) – *for uploading on MHA's website under AGMUT Cadre Management>Orders>transfer & posting.*

दिल्ली की जनता को गोपाल राय पर भरोसा नहीं, उपराज्यपाल हस्तक्षेप करें: देवेन्द्र यादव

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिन कारणों के खिलाफ विंटर एक्शन प्लान को कार्यान्वित करने की घोषणा की गई उन प्रदूषण कारकां पर नियंत्रण करने में आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 10 वर्षों में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि ऑड-इवन, रेड लाईट ऑन-गाड़ी ऑफ, और स्मॉग टावर जैसी केजरीवाल के मन की योजनाओं को लागू करने के बावजूद प्रदूषण सर्दियों में प्रदूषण 100 एक्यूआई से उपर ही रहता है।

यादव ने कहा कि दिल्ली के प्रदूषण नियंत्रण के मामले में उपराज्यपाल स्वयं हस्तक्षेप करें क्योंकि गोपाल राय के 14 सूत्री बिंदु धूल कण, वाहन प्रदूषण, टूटी सड़कों के धूल, पराली जलाना, खुले में कचरा जलाना, औद्योगिक प्रदूषण, पटाखों पर प्रतिबंध, ग्रीन वॉर रूम और ग्रीन ऐप, हॉट स्पॉट, वास्तविक समय स्रोत विभाजन अध्ययन, हरित आवरण/नवनीकरण बढ़ाना, ई-कचरा इको पार्क, केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों के साथ बातचीत और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) का कार्यान्वयन में कुछ नया नही है, हर वर्ष दिल्ली सरकार इन पर काम करती है परंतु खतरनाक जानलेवा प्रदूषण पर नियंत्रण करने में नाकाम साबित होती है। प्रदूषण से जुड़ी एक स्टडी के अनुसार वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली के बच्चों की आयु सीमा 12 साल कम हो गई है।

यादव ने कहा कि केजरीवाल सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए मिले फंड 742.69 करोड़ में से सिर्फ 29 प्रतिशत ही खर्च कर पाई है, प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोई ठोस कदम क्यों नही उठाया, गोपाल राय इसका जवाब दें? 24 करोड़ की लागत से बने स्मॉग टावर कोई काम नही कर रहे है। उन्होंने कहा कि आई.आई.टी. कानपुर सहित विभिन्न विशेषज्ञों से चर्चा हर साल करते है और पिछले कई वर्षों से कृत्रिम वर्षा जैसे कार्य भी करते रहे है, गोपाल राय की योजना में कुछ नया नही है, क्योंकि कृत्रिम वर्षा अनावश्यक और प्रभावहीन साबित रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदूषण का मुख्य कारण तीनों लैंड फिलों पर कूड़ा निस्तारण कार्यक्रम को गोपाल राय ने अपने विंटर एक्शन प्लान में शामिल क्यों नही किया?

यादव ने कहा कि केजरीवाल सरकार शुद्ध पर्यावरण की बात करके बयान देती है कि 2016 में साफ हवा वाले दिनां की संख्या 110 दिन थी जो 2023 में बढ़कर 206 दिन हो गई। अगर आंकड़े सही है तो अक्टूबर 2023 से मध्य फरवरी 2024 तक दिल्ली में प्रदूषण विश्व में नम्बर पर कैसे बनी रही है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार उपलब्धि रही कि राजधानी खतरनाक जानलेवा प्रदूषण में भी नम्बर रहती है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग की नाकामी रही कि पिछले एक महीने से भी अधिक समय तक 600 से अधिक पीयूसी केन्द्र पीयूसी सर्टिफिकेट के शुल्क में बढ़ोतरी की मांग को लेकर एक महीने से भी अधिक समय तक बंद रहे। दिल्ली प्रदेश प्रदूषण आयोग में वर्षों से आधे से अधिक पद रिक्त पड़े है जिनको सरकार भरना ही नही चाहती, जिसके कारण प्रदूषण रोकथाम का काम नही हो रहा

आप-बीजेपी को तगड़ा झटका, 100 से अधिक नेता कांग्रेस में हुए शामिल

दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले 100 से अधिक नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस का हाथ थामने वालों में मंगोल पुरी विधानसभा से वार्ड 50 से आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद कृष्ण परमाल वार्ड 51 से पूर्व पार्षद संजय ठाकुर गौरव शर्मा बसपा से सुरेंद्र जीतू और दीपक वार्ड 50 से भाजपा के एससी मोर्चा मंडल अध्यक्ष राजेश कुमार सहित अन्य लोग शामिल रहे।

नई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने शुक्रवार को भाजपा, आप और बसपा के कई नेताओं को कांग्रेस का पटकार पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार और पूर्व जिलाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह मुख्य रूप से मौजूद थे।

कांग्रेस का हाथ थामने वालों में मंगोल पुरी विधानसभा से वार्ड 50 से आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद कृष्ण परमाल, वार्ड 51 से पूर्व पार्षद संजय ठाकुर, गौरव शर्मा, बसपा से सुरेंद्र जीतू और दीपक वार्ड 50 से, भाजपा के एससी मोर्चा मंडल अध्यक्ष राजेश कुमार सहित अन्य लोग शामिल रहे।

नेताओं के कांग्रेस में आने से पार्टी को मिलेगी मजबूती: देवेंद्र यादव

देवेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपनी पार्टी के प्रति मोह भंग हो रहा है। इसीलिए कांग्रेस में शामिल हो रहे है। मंगोलपुरी विधानसभा के दो पूर्व पार्षद आने के बाद पार्टी को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी में शामिल होने वाले सभी लोगों को पार्टी में उचित सम्मान दिया जाएगा।

देवेंद्र यादव ने कहा कि जननायक एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के सिद्धांतों और कांग्रेस के विजन में ही दिल्ली की खुशहाली और समृद्धि का रास्ता निहित है। ऐसा अब सभी को विश्वास होने लगा है। इसी क्रम में दिल्ली कांग्रेस कार्यालय पर विशाल संख्या में 100 से अधिक भाजपा, आप और बसपा छोड़कर आए कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाई।

मोहभंग होने के बाद कांग्रेस में शामिल हो रहे लोग: देवेंद्र यादव

उन्होंने कहा, "आप के कई लोग कांग्रेस की विचारधारा में शामिल हो रहे हैं। 11 साल पहले, ये लोग दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त और विकसित बनाने की विचारधारा में शामिल हुए थे। हालांकि, इससे मोहभंग होने के बाद वे अब कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। मैं उन सभी का स्वागत करना चाहता हूं।"

सीबीआई की छापेमारी में सिविल डिफेंस का पूर्व कर्मचारी गिरफ्तार, हेड कांस्टेबल फरार

सुषमा रानी

सीबीआई ने शनिवार को उत्तरी दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में छापेमारी कर सिविल डिफेंस के एक पूर्व कर्मचारी को चार हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उसके साथ एक हेड कांस्टेबल भी था जो मौके से फरार हो गया। आरोपी की पहचान शैलेश कुमार के रूप में हुई है। इस मामले में पुलिस ने सीबीआई की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है।

नई दिल्ली। सीबीआई की टीम ने शनिवार सुबह बाहरी उत्तरी जिले की शाहबाद डेरी इलाके में छापा मारकर सिविल डिफेंस के एक पूर्व कर्मचारी को चार हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। सूत्रों की मानें तो उसके साथ एक हेड कांस्टेबल भी था, जो छापा पड़ते ही मौके से भाग निकला।

सिविल डिफेंस के पूर्व कर्मचारी की पहचान शैलेश कुमार के तौर पर हुई है। वहीं, हेड कांस्टेबल का नाम सामने आने के बाद थानाध्यक्ष पर गाज गिरी है।

ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर कोर्ट में CBI का बड़ा खुलासा, कोचिंग के मालिक पर जांच एजेंसी ने लगाए गंभीर आरोप

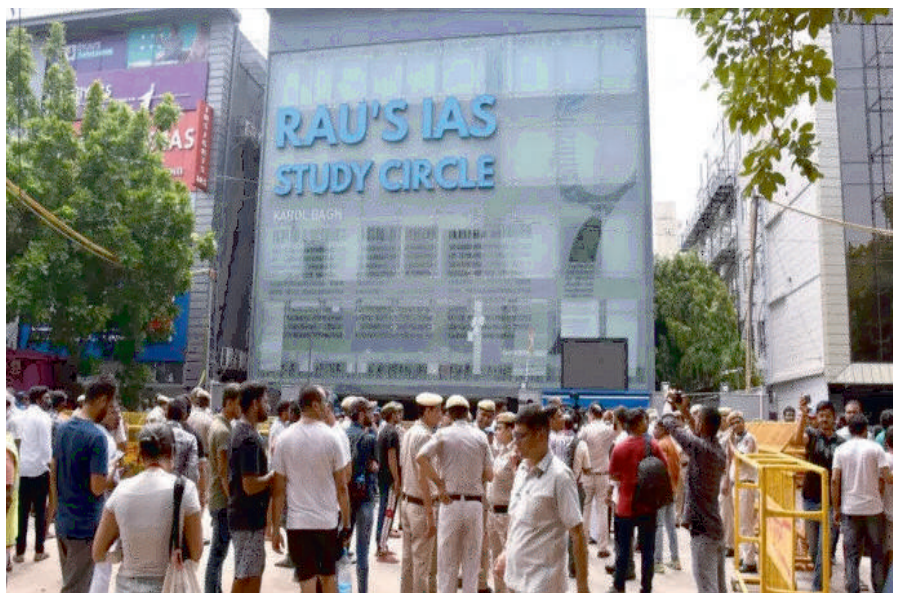

परिवहन विशेष न्यूज

ओल्ड राजेंद्र नगर राव आईएएस स्टडी सर्किल में हुए हादसे में कोर्ट ने बड़ा खुलासा करते हुए कोचिंग के मालिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि राव आईएएस के मालिक ने जानबूझकर बेसमेंट का इस्तेमाल किया था। इस मामले में छह लोगों को चार दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया है। पढ़िए पूरी खबर विस्तार से।

नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर राव आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में सिविल सेवा के तीन उम्मीदवारों की डूबने से हुई मौत के मामले में गिरफ्तार छह लोगों को चार दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि राव आईएएस के मालिक ने जानबूझकर बेसमेंट का इस्तेमाल किया था।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने कोचिंग के सीईओ अभिषेक गुप्ता, कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह, बेसमेंट के चार सह-मालिक तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह, सरबजीत सिंह और परविंदर सिंह को चार सितंबर तक हिरासत में भेज दिया।

दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत पहुंचे तिहाड़, कहा- CM केजरीवाल के नेतृत्व में हम जेल सुधार के लिए प्रतिबद्ध

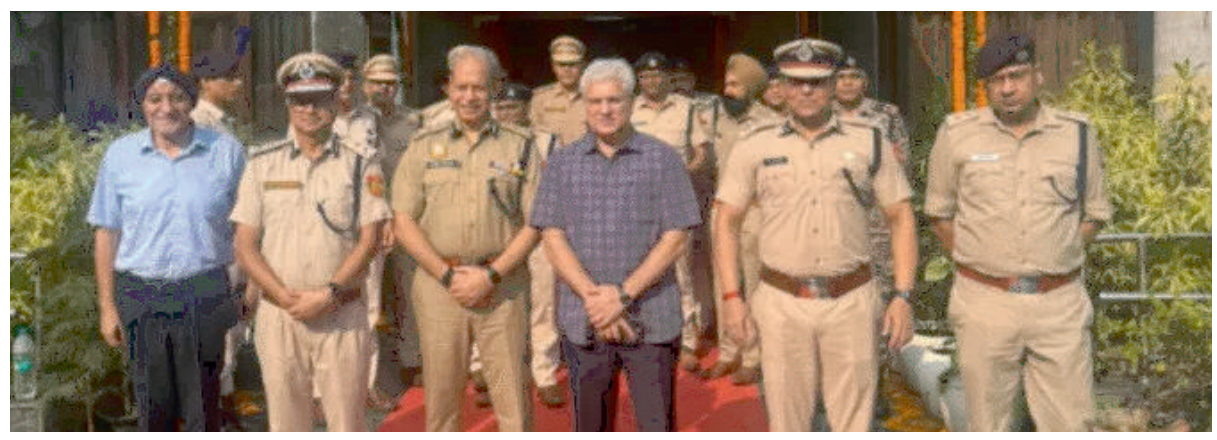

दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत ने अधिकारियों के साथ तिहाड़ जेल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान कैदियों को दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार कर्मचारियों के हित में और बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए। जेलों में व्यवस्थागत और व्यापक सुधार के लिए दिल्ली सरकार लगातार प्रयासरत और प्रतिबद्ध है। उन्होंने कैदियों को मिल रहे प्रशिक्षण पर भी संतोष जताया।

नई दिल्ली। दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत ने शनिवार को तिहाड़ जेल नंबर-3 और 6 का दौरा किया। इसका उद्देश्य जेलों के अंदर सुधारात्मक व्यवस्था में बदलाव के प्रति दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करना था। इस दौरान गृह मंत्री ने कैदियों के रहने की स्थिति में सुधार लाने, कर्मचारियों के कल्याण और सुविधाओं को और बेहतर करने की दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।

इस अवसर पर कैलाश गहलोत के साथ गृह सचिव चंचल यादव, जेल महानिदेशक सतीश गोलचा, अतिरिक्त महानिरीक्षण कारागार डॉ. अजय कुमार बिष्ट, जेल उप महानिर्देशक राजीव सिंह समेत जेल विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

कैदियों को दी जा रही बुनियादी सुविधाओं का निरीक्षण

कैलाश गहलोत ने कहा कि जेल की स्थितियों में सुधार के लिए दिल्ली सरकार के चल रहे प्रयासों के तहत मैंने एशिया के सबसे बड़े जेल परिसर तिहाड़ का दौरा किया। इस दौरान वहां मैंने कैदियों को दी जा रही बुनियादी सुविधाओं का निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार जेलों में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। तिहाड़ जेल का हमारा यह दौरा जेल की स्थितियों में सुधार लाने और यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक और कदम है कि कैदियों को आवश्यक संसाधन मुहैया कराए जाएं, जिससे कि वो खुद को सुधारें।

जरूरी संसाधन उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी: गहलोत

उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में सुधार करने की क्षमता होती है और उसे ऐसा करने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है। मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार, जेल अधिकारियों और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से हम एक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज का निर्माण कर सकते हैं।

कैदियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण पर बोले गहलोत

सेंट्रल जेल नंबर 6 (महिला बैरक) के निरीक्षण के दौरान गृह मंत्री कैलाश गहलोत ने व्यवसायिक प्रशिक्षण इकाई, सिलाई, आभूषण उत्पादन और क्रेच समेत कई प्रमुख क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने कैदियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देने वाले गैर सरकारी संगठनों की सरहाना की और इस बात पर बल दिया कि कैसे ये कार्यक्रम जेल से बाहर आने के बाद कैदियों के पुनर्वास में मददगार साबित होंगे।

इसके बाद गृह मंत्री ने सेंट्रल जेल नंबर 3 का भी दौरा किया, जहां उन्होंने गौशाला, लंगर (सामुदायिक रसोई) और 120 बिस्तरों वाले अस्पताल का निरीक्षण किया। मंत्री ने कैदियों के लिए तैयार किए गए भोजन की स्वच्छता और गुणवत्ता की सराहना की और अस्पताल की क्षमता और सुविधाओं के विस्तार की जरूरत पर बल दिया।

नोएडा में होगा बड़ा आंदोलन! किसानों ने प्राधिकरण के अधिकारियों को दी चेतावनी

परिवहन विशेष न्यूज

Farmers Protest नोएडा में किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट नहीं आने से किसान नाराज हैं। भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ग्रुप के किसानों ने नोएडा प्राधिकरण कार्यालय पर सीईओ डॉ. लोकेश एम के साथ बैठक की और चेतावनी दी कि अगर जल्द ही कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे।

नोएडा। किसानों की समस्याओं को निस्तारण करने के लिए शासन के निर्देश पर हाई पावर कमेटी गठित हुई थी, लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आने पर किसानों में कड़ा ऐतराज जताया है। शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ग्रुप के किसानों ने नोएडा प्राधिकरण कार्यालय पर सीईओ डॉ. लोकेश एम के साथ बैठक की।

इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष पवन खटाना ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती तो किसान बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके जिम्मेदार स्वयं अधिकारी होंगे। किसानों की ओर से लंबे समय से मांग की जा रही है, लेकिन शासन प्रशासन समाधान करने को तैयार नहीं है।

पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत भूखंड

सभी किसानों को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत भूखंड, किसानों की भूमि अधिग्रहण व सहमति प्रतिकर में बढ़ोतरी, 50 प्रतिशत व्यावसायिक गतिविधि, आबादियों का संपूर्ण निस्तारण, क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार, पुश्तैनी गैर पुश्तैनी का भेदभाव खत्म, प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों का स्मार्ट विलेज के तहत सुंदरीकरण कराया जाए।

याकूबपुर, गुलावली, सिलारपुर, नंगली वाजिदपुर, नवादा, वजीदपुर गांवों में बारात घर, सीवर, पानी, पार्क का निर्माण कराया जाए। इस मौके पर अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजय कुमार खत्री, भूलेख विभाग ओएसडी महेंद्र प्रसाद, क्रांति शेखर सिंह, जन स्वास्थ्य विभाग महाप्रबंधक एसपी सिंह व नियोजन विभाग महाप्रबंधक मीना भार्गव, सिविल विभाग उप महाप्रबंधक विजय कुमार रावल, किसान नेता राबिन नागर समेत अन्य मौजूद रहे।

प्राधिकरण का नुकसान कर वालों पर होगी कार्रवाई

बिल्डरों के चंगुल में फंसे तीन लाख फ्लैट खरीदारों को जल्द से जल्द राहत दिलाने और आशियाने का मालिकाना हक के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। जिन बिल्डरों को प्राधिकरण का नुकसान कर अब तक अधिकारियों व कर्मचारियों ने लाभ पहुंचायाहे। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे आम जन का विश्वास शासन सतर पर मजबूत हो।

यह आदेश लोक लेखा समिति (पीएसी) ने शासन को दिया है, स्पष्ट किया है कि सचिव स्तर की दो जांच कमेटियों का गठन किया जाए। इसमें से एक जांच कमेटी ग्रुप हाउसिंग और दूसरी स्पोर्ट्स सिटी के प्रकरण का निपटान करे। यहीं नहीं इन्हीं कमेटियों की ओर से दोषियों को चिह्नित करने का काम भी होगा।

इन प्रकरण की जांच रिपोर्ट दो माह में पीएसी के सामने रखनी होगी। बृहस्पतिवार को लखनऊ में लोक लेखा समिति (पीएसी) की ओर से स्पोर्ट्स सिटी, ग्रुप हाउसिंग, व्यावसायिक, नियोजन विभाग से जुड़े कामकाज पर लगी कैग (सीएजी) की आपत्तियों के निस्तारण के लिए नोएडा प्राधिकरण अधिकारियों को बुलाया था।

पलवल में स्कूल बस पलटी, 40 बच्चे थे सवार; बाल-बाल टला बड़ा हादसा

पलवल के हसनपुर खंड में मंगलवार को गांव भिड़ूकी स्थित नारायण विद्या निकेतन स्कूल की एक बस अनियंत्रित होकर खेतों में पलट गई। इस हादसे का कारण सामने से ट्रैक्टर आ जाना था। बता दें हसनपुर माहोली चौडरस आदि गाँवों के लगभग 30 से 40 बच्चे सवार थे। गनीमत रही कि बच्चों को कोई गंभीर चोटें नहीं आई।

पलवल। मंगलवार को हसनपुर खंड के गांव भिड़ूकी में स्थित नारायण विद्या निकेतन स्कूल की बस यूपी के गांव शाहपुर से बच्चों को लेकर बच्चों को लेकर आ रही थी सामने से ट्रैक्टर आ जाने के कारण बस अनियंत्रित हो गई तथा खेतों में पलट गई।

बस मे 30 से 40 बच्चे थे सवार

हादसे में हसनपुर ,माहोली,चौडरस आदि गांवों के लगभग 30 से 40 बच्चे सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस ने दो पलटा खाए और खेतों में जा गिरी। मौके पर उपस्थित लोगों ने बस के शीशे तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला।

बस पलटने की सूचना मिलते ही बच्चों के परिजन पहुंचे

गनीमत रही कि बच्चों को कोई गंभीर चोटें नहीं आईं। बस पलटने की सूचना मिलते ही बच्चों के स्वजन घटना स्थल की ओर दौड़ पड़े। सभी बच्चों को हल्की चोटें आईं, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।

उधर, हसनपुर थाना प्रभारी संजीव कुमार का कहना है कि हमें स्कूल बस पलटने की कोई सूचना नही मिली है। अगर कोई शिकायत आएगी तो उचित कार्रवाई की जाएगी।

ईडी ने सनस्टार की 294.19 करोड़ की संपत्तियां कीं जब्त, जांच में खुल सकते हैं और कई राज

ED Action ईडी ने हरियाणा के गुरुग्राम में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम ने सनस्टार की 294.19 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं। अभी ईडी की कार्रवाई जारी है और टीम और भी संपत्तियां जब्त कर सकती हैं। ED ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत यह कार्रवाई की है। पढ़िए क्या-क्या जब्त किया गया है?

गुरुग्राम। ED Action प्रवर्तन निदेशालय (ईडी ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड और अन्य संबंधित कंपनियों की 294.19 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। यह संपत्तियां भूमि, इमारतों, फ्लैट्स और फिक्स्ड डिपाजिट रसीदों (एफडीआर) के रूप में है।

ईडी की इस कार्रवाई का मकसद उन संपत्तियों को सुरक्षित करना है, जो कथित तौर पर अवैध गतिविधियों और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए हासिल की गई थीं। सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड और इससे जुड़े अन्य व्यक्तियों पर आरोप है कि उन्होंने धोखाधड़ी के जरिए बैंक से ऋण लिया और उसके बाद धन का दुरुपयोग करते हुए उसे विभिन्न संपत्तियों में निवेश किया।

कंपनी ने कई वित्तीय अनियमितताएं की हैं

इस मामले की जांच ईडी ने शुरू की थी, जब उन्हें जानकारी मिली कि कंपनी ने कई वित्तीय अनियमितताएं की हैं। जांच के दौरान यह पाया गया कि कंपनी और इससे जुड़े लोग अवैध रूप से एकत्र धन को छुपाने और उसे वैध दिखाने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल कर रहे थे।

अभी जारी है ईडी की कार्रवाई

इसके अलावा, कंपनी के नाम पर कई फ्लैट्स और एफडीआर भी जब्त किए गए हैं। ईडी की माने तो जांच अभी भी जारी है। इस मामले में और भी संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं।

यूपी सरकार का आदेश न मानने पर प्राधिकरण के 17 अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई, 14 सस्पेंड

उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों को दरकिनार करना नोएडा ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों को भारी पड़ गया। इन प्राधिकरण के 17 अधिकारी और कर्मचारियों कार्रवाई की गई। इनमें से तीन पर विभागीय जांच का आदेश जारी किया है। साथ ही 14 को निलंबित कर दिया गया। शुक्रवार देर रात निलंबित करने का आदेश जारी कर पत्र तीनों प्राधिकरणों को भेज दिया।

साहिबाबाद। नोएडा। नोएडा-ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण (Yamuna Authority) में तैनात 17 अधिकारी कर्मचारियों को शासन का निर्देश दरकिनार करना महंगा पड़ गया है। तबादले के बाद भी अपनी मर्जी से पुराने विभागों में जमे रहे, नई तैनाती पर भी नहीं पहुंचे और न ही नई तैनाती पर जाने का कारण ही अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग को स्पष्ट किया।

ऐसे में अनुशासनहीनता करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को विभाग के प्रमुख सचिव अनिल सागर ने शुक्रवार देर रात निलंबित करने का आदेश जारी कर पत्र तीनों प्राधिकरणों को भेज दिया। देर रात जारी इस विभागीय आदेश में तीनों प्राधिकरण में अफरा-तफरी मच गई है, क्योंकि 14 अधिकारियों-कर्मचारियों को निलंबित करने के साथ तीन अधिकारी की विभागीय जांच का आदेश शामिल है।

यूपी सरकार के मंत्री ने की थी बैठक

पिछले दिनों औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने लखनऊ में नोएडा प्राधिकरण की समीक्षा बैठक बुलाई थी। इसमें मंत्री ने नाराजगी जताई थी और चेतावनी दी कि तबादला होने के बाद भी जो अधिकारी-कर्मचारी विभागों में जमे हैं, उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा।

तबादले को नहीं लिया गंभीरता से

उसके बाद भी तबादला वाले अधिकारी कर्मचारियों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद अंडर ट्रांसफर वाले अधिकारी कर्मचारी की पत्रावली को मंत्रालय में तलब कर लिया गया। निलंबित होने वालों में यमुना प्राधिकरण में प्रबंधक अजब सिंह भाटी शामिल है। हालांकि पांच लोगों के नाम अभी पत्र विभागों में नहीं पहुंचे हैं। इसलिए आज उनके पत्र जारी होने संभावना है।

नोएडा प्राधिकरण में निलंबित अधिकारी-कर्मचारी

- विजेंद्र पाल सिंह कोमर (निजी सचिव)
- नरदेव (सहायक विधि अधिकारी)
- सुशील भाटी (सहायक विधि अधिकारी)
- यूएस फारूख (सहायक प्रबंधक नियोजन)
- सुमित ग्रोवर (प्रबंधक नियोजन)
- प्रमोद कुमार (लेखाकार)

नोएडा में इन पर होगी विभागीय जांच

- विजय कुमार रावल (उपमहाप्रबंधक सिविल)
- सतेंद्र गिरी (वरिष्ठ प्रबंधक)
- प्रेम कुमार (सहायक प्रबंधक नियोजन)

ग्रेटर नोएडा में निलंबित होने वाले अधिकारी कर्मचारी

- सुरेंद्र कुमार (सहायक प्रबंधक)
- आरए गौतम (वरिष्ठ प्रबंधक)
- विजय कुमार बाजपेई (प्रबंधक)

कोलकाता रेप-मर्डर केस ने एक बार फिर हमारी प्रशासनिक कमजोरियों को उजागर कर दिया, आखिर ऐसा कबतक?

आपने देखा होगा कि एक ओर तृणमूल कांग्रेस नेत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि पश्चिम बंगाल में आग लगाने की साज़िश हो रही है। अगर पश्चिम बंगाल जलेगा तो असम, पूर्वोत्तर राज्य, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और दिल्ली भी जलेंगे।

दिल्ली निर्भया बलात्कार हत्याकांड के लगभग 12 वर्ष बाद कोलकाता रेप-मर्डर केस की पुनरावृत्ति भारतीय जनतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था पर गम्भीर सवाल खड़ा करती है। वहीं, इन दोनों मामलों को जरूरत से ज्यादा तूल देने और अन्य समकक्ष घटनाओं की उपेक्षा करने में हमारे राजनेताओं और मीडिया की भूमिका भी संदेह के कठघरे में है! कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल में जिस तरह की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, उससे हर कोई भयभीत नहीं तो चिंतित अवश्य लग रहा है, क्योंकि यह सबकुछ भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले कोलकाता में घट रहा है, जिससे देर-सबेर हमारी संस्कृति भी अछूती नहीं बचेगी।

लिहाजा, सुलगता हुआ सवाल यह है कि आखिर में ऐसी बदसूरत घटनाएं कब तक थमेंगी? और यदि नहीं रुकेंगी तो फिर समकालीन संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की जरूरत ही क्या है? क्योंकि यह व्यवस्था सबके वेतन-भत्ते की गारंटी तो देता है, लेकिन किसी भी बड़ी या छोटी लापरवाही के बाद जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय नहीं करता है! यही वजह है कि सत्ताधारी वर्ग मजे में रहता है और जनता बिल्कुल अनाथ की मानिंद। इसलिए अकसर यह सवाल जेहन में उठता है कि आखिर में क्यों नहीं उस वैकल्पिक प्रशासनिक व्यवस्था पर विचार किया जाए, जहां इस तरह के जघन्य अपराध करने की हिमाकत ही कोई कर नहीं पाए। क्या यह संभव है? नई विश्व व्यवस्था के नजरिए से कतई असंभव नहीं है।

आपने देखा होगा कि एक ओर तृणमूल कांग्रेस नेत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि पश्चिम बंगाल में आग लगाने की साज़िश हो रही है। अगर पश्चिम बंगाल जलेगा तो असम, पूर्वोत्तर राज्य, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और दिल्ली भी जलेंगे। वहीं, दूसरी ओर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का बयान आया है कि चिंतित हूँ और डरी हुई हूँ। इससे इस मामले की गम्भीरता और ज्यादा बढ़ चुकी है। सबको अंदेशा है कि पश्चिम बंगाल की नाजुक परिस्थितियों के मद्देनजर वहां पर कभी भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जो जरूरी भी है, वहां के निरन्तर घट रहे घटनाओं के मद्देनजर। विरोध-प्रदर्शन, बंद और हिंसा की घटनाओं के बीच प्रदेश के राज्यपाल सीवी आनंद बोस जब दिल्ली के लिए रवाना हो गए, तो इससे इन अटकलों को और अधिक बल मिला है।

बता दें कि गत गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार और वरिष्ठ नेताओं ने राज्यपाल से मुलाक़ात कर एक ज्ञापन सौंपा था और उनसे 'अनुरोध' किया था कि वह पश्चिम बंगाल में 'संवैधानिक मूल्यों की रक्षा' करें। इससे पहले गत 27 अगस्त को राज्यपाल ने भी एक बयान जारी कर 'पश्चिम बंग छात्र समाज' के बुलाए गए 'नबन्ना मार्च' (सचिवालय पर प्रदर्शन) के दौरान हुई हिंसा को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की थी।

लिहाजा, यहां पर एक और सुलगता हुआ सवाल उठता है कि क्या दिल्ली की जमी-जमाई मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को निर्भया कांड की आड़ में 'निपटाने' योग्य माहौल बनाने के बाद अब बंगाल की जमी-जमाई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी कोलकाता दुष्कर्म हत्याकांड के बहाने 'निपटाने' योग्य माहौल बनाने की जिम्मेदारी कतिपय लोगों ने ले ली है, जैसा कि मीडिया के माहौल को देखकर प्रतीत हो रहा है। या फिर यह सब एक लोकतांत्रिक दस्तूर बन चुका है, जो किसी भी घटना के बाद नजर आता है।

आखिर यह कौन नहीं जानता कि देश में चल रहे तमाम तरह के संगठित अपराधों को सत्ताधारी दल और प्रशासनिक महकमे के असरदार लॉबी का परोक्ष शह प्राप्त होता है, जिसकी कड़ी से जुड़े लोग यदा-कदा जघन्य से जघन्य अपराध करने तक से भी कोई गुरेज नहीं करते। इस पूरे प्रकरण में डॉ घोष की चर्चित भूमिका के दृष्टिगत यहां भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। इसलिए पुनः यही बात उठी है कि लोकतंत्र और बहुमत जुगाड़ के नाम पर हमारे सत्ताधारी नेता ऐसे तत्वों के खिलाफ आखिर कबतक अपने मुंह बन्द रखेंगे? क्योंकि जब वो विपक्ष में होते हैं तो ऐसे तत्वों के खिलाफ खूब बोलते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हें सांप सूंघ जाता है और ऐसे तत्वों के खिलाफ खामोशी की चादर ओढ़ लेते हैं। इसलिए अब एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था की जरूरत है जहां लोकतंत्र और बहुमत के जुगाड़ के खातिर कोई भी सियासी या सामाजिक व्यक्ति गलत को नजरअंदाज करने की हिमाकत ही नहीं कर पाए और यदि करे भी तो उसकी भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहे। ऐसी व्यवस्था अभी तो सम्भव प्रतीत नहीं होती!

वहीं, पश्चिम बंगाल की राजनीति पर नज़र रखने वाले बताते हैं कि मुख्यमंत्री के हालिया अटपटे बयानों से यह प्रतीत हो रहा है कि आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार और हत्या की घटना के बाद आम लोगों में पनपे आक्रोश से ममता बनर्जी दबाव में हैं। उन्हें इतने दबाव में पहली बार देखा जा रहा है। वहीं कुछ ऐसे भी हैं, जिन्हें लगता है कि वह इससे जल्द ही उबर जाएंगी। ये सही है कि ये पहली बार नहीं है, जब ममता बनर्जी को आंदोलन का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन वो मानते हैं कि इस बार वो दबाव में इसलिए दिख रही हैं क्योंकि आम लोगों के बीच उनके शासन चलाने के तरीक़े की आलोचना हो रही है।

खासकर महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार का ये रिकॉर्ड नहीं रहा है कि उसने किसी पीड़िता को इंसाफ़ दिलवाया हो या फिर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वालों को कभी क़ानूनी शिकंजे में जकड़ा हो। इसलिए आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद आम लोगों और ख़ास तौर पर आम महिलाओं का ग़ुस्सा फूट पड़ा, जिसका तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेताओं, राज्य सरकार या ख़ुद ममता बनर्जी को अंदाज़ा नहीं था।

बताया गया है कि जिस तरह से कोलकाता पुलिस की भूमिका इस मामले को लेकर रही, जैसे एफ़आईआर दर्ज करने में देरी, पीड़िता के माता-पिता को ग़लत जानकारी दिया जाना या फिर घटना में 'सिविल वॉलंटियर' का शामिल होना-ये सब लोगों के ग़ुस्से को बढ़ाता रहा। कई चीज़ें एक साथ हुईं। जैसे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और अन्य वरिष्ठ प्रशासकों की भूमिका। फिर अभियुक्त संजय राय पुलिस का ही हिस्सा है, बतौर एक सिविल वॉलंटियर। फिर 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात में आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में विरोध कर रहे जूनियर डॉक्टरों पर जो भीड़ का हमला हुआ, उससे कोलकाता पुलिस की छवि तो ख़राब हुई ही साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार भी आम लोगों के सवालों के घेरे में आ गई।

एक ओर कोलकाता रेप-मर्डर केस के बाद भाजपा सड़कों पर है तो इस मामले पर ममता की पार्टी में बाग़ी रुख़ के बीच अभिषेक बनर्जी की चुप्पी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कोलकाता में ममता सरकार के ख़िलाफ़ विरोध-प्रदर्शन लगातार जारी है। पीड़िता के परिवार और जूनियर डॉक्टरों के आक्रोश के बावजूद आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष पर प्रशासनिक कार्रवाई ना करते हुए, उनको कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का प्रिंसिपल बना दिया गया। वो भी तब जब उनके ख़िलाफ़ 'प्रशासनिक अनियमितताओं' के आरोपों की लिखित शिकायत राज्य सरकार के पास मौजूद थी।

यही वजह है कि पश्चिम बंगाल सरकार के रुख़ को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणियां कीं। इससे लोगों के बीच राज्य सरकार और ममता बनर्जी को लेकर आक्रोश भड़क गया। ऐसा पहली बार भी हुआ है कि आम लोगों के साथ-साथ, अलग-अलग ही सही, सभी विपक्षी दल, जैसे कांग्रेस और वाम दलों ने भी ममता बनर्जी के ख़िलाफ़ इस घटना के बाद मोर्चा संभाला। दरअसल प्रशासन के ख़िलाफ़ लोगों का जो ग़ुस्सा फूट पड़ा, वह सिर्फ़ एक घटना की वजह से नहीं है बल्कि कई मुद्दे हैं, जिनको लेकर लोगों में आक्रोश पहले से ही पनप रहा था।

जानकार बताते हैं कि पार्टी के अंदर ही अभिषेक बनर्जी ने कई बार यह मुद्दा उठाया कि राज्य प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा है। प्रशासन जिस तरह से चल रहा है, उसको लेकर भी लोगों में पहले से ही ग़ुस्सा था। जैसे जन प्रतिनिधियों की थाना प्रभारियों और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के सामने कुछ चलती ही नहीं थी। वैसे देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में लोगों का राजनीतिक दलों पर से ही भरोसा कम होता जा रहा है। क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं की भाषा अगर आप सुनें तो एक तरह से उकसाने वाली भाषा बोलते हैं। पहले ये आरोप वाम दलों पर लगते थे मगर अब तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं पर भी इसी तरह के आरोप लग रहे हैं। इसलिए वो ग़ुस्सा आम लोगों में पनप तो रहा था, लेकिन आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद लोगों के सब्र का बांध टूट गया।

वहीं, जानकार कहते हैं कि जिस तरह का दबाव ममता बनर्जी पर पिछले एक-दो दिनों में बन गया है, उससे बाहर निकलने के लिए वह आक्रामक तेवर भी दिखा रही हैं। जिस तरह राज्य सरकार ने भारत बंद के दौरान गिरफ्तारियां की हैं या फिर 'पश्चिम बंग छात्र समाज' के 'नबन्ना मार्च' (सचिवालय मार्च) करने वालों पर क़ानूनी कार्रवाई की है, उससे वह फिर से चीज़ों को अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रही हैं।

तृणमूल कांग्रेस के नेता तो यहां तक कहते हैं कि हाल ही में लोकसभा के चुनावों में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए हर हथकंडा अपनाया था, परन्तु जनता ने उन्हें नकार दिया इसलिए अब आर.जी. कर की घटना को लेकर बीजेपी अपनी राजनीति फिर से चमकाने की कोशिश कर रही है। वह राज्य में हिंसा और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। इस मामले में राज्य सरकार ने घटना के फौरन बाद कार्रवाई की और एक अभियुक्त को कुछ ही घंटों में पकड़ लिया। इसके बाद मामला सीबीआई के पास चला गया है, तो सवाल उन पर उठता है कि उन्होंने इतने दिनों में जांच में क्या प्रगति की है? भाजपा के लोग इस घटना को लेकर राज्य को अशांत करने की साज़िश कर रहे हैं, जिसका ममता बनर्जी ने भांडा फोड़ा है। तृणमूल नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार और ख़ास तौर पर बीजेपी पश्चिम बंगाल को 'राज्यपाल के ज़रिए अस्थिर करने की कोशिश' कर रही है। इससे पहले भी संदेशखाली को लेकर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल सरकार के ख़िलाफ़ माहौल बनाने की कोशिश की थी।

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV Drive the Future

दिल्ली सरकार ने 01 से 28 अगस्त के बीच 1,777 ई-रिक्शा किए जब्त

परिवहन विशेष न्यूज

पीटीआई-भाषा फीड से प्रकाशित खबर के अनुसार उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के निर्देश के बाद दिल्ली में 01 से 28 अगस्त के बीच करीब 1,700 गैर-पंजीकृत ई-रिक्शा जब्त कर कबाड़ गोदामों में भेजे गए हैं।

उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली सरकार को इन रिक्शा के ₹अवैध संचालन₹ पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया था। दिल्ली को भीड़-भाड़ से मुक्त बनाने के लिए 08 अगस्त को उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान परिवहन विभाग को गैर-पंजीकृत रिक्शा जब्त करने का निर्देश दिया गया था।

पिछले कुछ सालों में बैटरी से चलने वाले ये ई-रिक्शा सड़कों पर खूब देखे गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि आउटर रिंग रोड और इनर रिंग रोड पर ई-रिक्शा जब्त करने के लिए 39 टीमें तैनात की गई थीं। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के निर्देश के बाद ऐसे वाहनों की जब्ती के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है।

इन वाहनों को जब्त कर 'रोड रोलर्स' या एक्सकेवेटर मशीनों से कुचला जाता है और पंजीकृत कबाड़ गोदामों को सौंप दिया जाता है। परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार जनवरी से मार्च के बीच केवल 134 ई-रिक्शा जब्त किए गए। अप्रैल से जुलाई के दौरान यह संख्या बढ़कर 732 हो गई। आंकड़ों के अनुसार 01 से 28 अगस्त के बीच 1,777 ई-रिक्शा जब्त किए गए।

स्मार्टफोन से खुलेंगे नए हुंडई अलकज़ार के दरवाजे, मिलेंगे 70 से ज्यादा कनेक्टेड कार फीचर

परिवहन विशेष न्यूज

2024 Hyundai Alcazar Tech Explained नई हुंडई अल्काजार को 9 सितंबर को भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा। इसके इंटीरियर का खुलासा पहले ही कंपनी कर चुकी है अब इसमें कौन-कौन से तकनीक मिलेंगे। इसके बारे में कंपनी ने बताया है। जिसके मुताबिक 2024 Hyundai Alcazar में टच-बेस्ड कंट्रोल पैनल के साथ डुअल जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल फीचर्स के साथ ही कई 70 से ज्यादा कनेक्टेड कार फीचर्स मिलेंगे।

नई दिल्ली। हुंडई ने हाल ही में अपनी नई एसयूवी 2024 Hyundai Alcazar के इंटीरियर का खुलासा किया है। इसके साथ ही कंपनी की तरफ से यह भी बताया गया है कि यह 9 सितंबर को लॉन्च होने जा रही है। कंपनी ने अब इसमें मिलने वाले मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है। आइए जानते हैं 6 और 7-सीटर एसयूवी में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ तकनीकों के बारे में।

2024 Hyundai Alcazar: डिजिटल चाभी

नई हुंडई अल्काजार में NFC तकनीक वाली इसकी डिजिटल चाभी का फीचर दिया गया है। इस फीचर की मदद से ड्राइवर अपने मोबाइल या स्मार्टवॉच का इस्तेमाल करके गाड़ी के दरवाजे को ओपन कर सकेंगे। इतना ही नहीं इसकी मदद से वह गाड़ी को स्टार्ट भी कर सकते हैं। इस फीचर की मदद से ड्राइवर अपनी डिजिटल चाभी को तीन अलग-अलग यूजर्स के साथ शेयर करने या एक साथ सात डिवाइस को लिंक कर सकेंगे।

2024 Hyundai Alcazar: डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

नई हुंडई अल्काजार में 10.25 इंच की दो स्क्रीन दी गई है, जिसमें एक इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है। इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम इन-बिल्ट नेविगेशन के साथ आता है। इसमें 10 क्षेत्रीय और 2 अंतरराष्ट्रीय भाषाएं दिए गए हैं। इसमें टच-बेस्ड कंट्रोल पैनल के साथ डुअल जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है।

2024 Hyundai Alcazar: कनेक्टिविटी

नई हुंडई अल्काजार में 70 से ज्यादा कनेक्टेड कार फीचर दिए हैं, जो स्मार्ट डिवाइस के साथ इंटेरोगेशन की सुविधा देते हैं। इसमें 270 से ज़्यादा एम्बेडेड वॉयस कमांड दिए गए हैं, जो बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी काम करते हैं। यह हिंदी और हिंग्लिश दोनों को सपोर्ट करते हैं। इतना ही नहीं नई अल्काजार में लाइवली फ़ॉरेस्ट, रेनी डे और सिटी एट डॉन जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

2024 Hyundai Alcazar: फीचर्स

नई हुंडई अल्काजार के केबिन को पहले से बेहतर बनाया गया है। केबिन में ड्राइवर के कंसोल पर एक मैग्नेटिक पैड और बीच की सीटों के लिए एक वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है। नई SUV में वॉयस-इनेबल्ड पैनोरमिक सनरूफ, रेन-सेंसिंग वाइपर और 8-स्पीकर बोस प्रीमियम साउंड सिस्टम दिया गया है।

त्योहारी सीजन में धूम मचाने आ रही हैं 03 बेहतरीन ईवी कारें

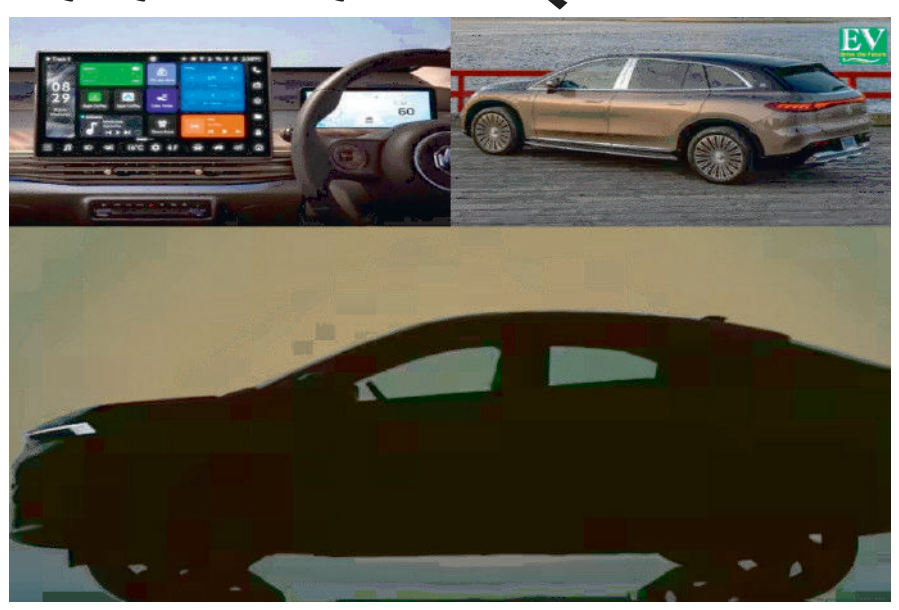

परिवहन विशेष न्यूज

सितंबर में कई त्योहार आने वाले हैं। इसके साथ ही भारतीय ऑटो सेक्टर नई ईवी कार लॉन्च की तैयारी कर रहा है। एमजी, मर्सिडीज-बेंज और टाटा मोटर्स समेत ऑटोमेकर अपने नए उत्पाद लॉन्च करने के लिए बाजार तैयार कर रहे हैं।

कॉमेट और जेडएस ईवी के बाद एमजी मोटर इंडिया अपना तीसरा इलेक्ट्रिक वाहन, विंडसर ईवी लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसकी लॉन्चिंग की तारीख 11 सितंबर है। यह वुलिंग क्लाउड ईवी का नया नाम होगा। वुलिंग क्लाउड ईवी कई देशों में 50.6kWh बैटरी पैक के साथ उपलब्ध है, जो 460 किमी की रेंज प्रदान करता है, और 37.9kWh यूनिट 360 किमी की रेंज प्रदान करता है।

भारत में सबसे ज़्यादा मांग वाली लग्जरी वाहन निर्माता कंपनी मर्सिडीज़-बेंज, मेबैक EQS SUV लॉन्च करेगी, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मर्सिडीज़-मेबैक EQS 680 दूसरे देशों में दो इलेक्ट्रिक मोटर और 107.8kWh बैटरी पैक के साथ उपलब्ध है, जो इसे 600 किलोमीटर तक चलने में सक्षम बनाता है।

टाटा मोटर्स 2 सितंबर, 2024 को अपनी नई कर्व लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसमें तीन इंजन विकल्प होंगे: 118 bhp और 260 Nm टॉर्क वाला 1.5-लीटर डीजल यूनिट, 125 bhp और 225 Nm टॉर्क वाला नया 1.2-लीटर TGDi टर्बो-पेट्रोल इंजन और 120 bhp और 170 Nm टॉर्क वाला 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल मोटर।

रांची जिला ई-रिक्शा संघ के अध्यक्ष ने हाईकोर्ट में दायर की जनहित याचिका

रांची नगर निगम, रांची ट्रैफिक, झारखंड सरकार, परिवहन विभाग और निगम चालान, कोर्ट चालान, ट्रैफिक चालान की गलत व्यवस्था के कारण रांची जिले में ई-रिक्शा चालकों को परिचालन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

इस प्रकार की समस्या को लेकर रांची जिला ई-रिक्शा संघ के अध्यक्ष मोहम्मद जावेद ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और जल्द ही अगली सुनवाई करेगा।

ठुकराल इलेक्ट्रिक बाइक्स ने एल5 और एल3 फाइनेंसिंग के लिए लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस के साथ की साझेदारी

परिवहन विशेष न्यूज

ठुकराल इलेक्ट्रिक बाइक्स और लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस के बीच साझेदारी का उद्देश्य सभी राज्यों में टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन समाधानों में योगदान करते हुए इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर तक पहुंच को बढ़ाना है।

ठुकराल इलेक्ट्रिक बाइक्स के सीईओ इशांक सुनेजा ने कहा कि इस साझेदारी से कंपनी ग्राहकों को बेहतर वित्तीय समाधान प्रदान करने में सक्षम होगी, जिससे बेहतर कमाई के अवसर पैदा होंगे।

उन्होंने कहा कि एल5 और एल3 दोनों श्रेणियों में कंपनी के इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर शक्तिशाली लिथियम-आयन बैटरी और मोटर से लैस हैं, जो उन्हें विभिन्न लोडिंग कार्यों के लिए अत्यधिक बहुमुखी बनाता है। ये वाहन ढुलाई और यात्री परिवहन दोनों के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं।

लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस के प्रवक्ता ने कहा कि यह साझेदारी एक गेम-चेंजर का प्रतीक है, जो इलेक्ट्रिक वाहन वित्तपोषण अनुभव को सरल और बेहतर बनाती है। यह बेहतर वित्तपोषण विकल्प और निर्बाध बदलाव प्रदान करने के बारे में है, जो अंततः हमारे ग्राहकों के लिए चीजों को सरल और बेहतर बनाती है।

ऑडी इंडिया इलेक्ट्रिक कारों की शुरू करने वाली है असेंबली

परिवहन विशेष न्यूज

लक्जरी वाहन निर्माता कंपनी ऑडी इंडिया इलेक्ट्रिक वाहनों की स्थानीय असेंबली शुरू करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो कंपनी भारत में कम कीमत पर वाहन उपलब्ध करा पाएगी और इससे उसका ग्राहक आधार बढ़ाने में मदद मिलेगी। ऑडी फिलहाल देश में ईवी की पूरी रेंज का आयात करती है। इनमें क्यू8 50 ई-ट्रॉन, क्यू8 55 ई-ट्रॉन, क्यू8 स्पोर्टबैक 50 ई-ट्रॉन, क्यू8 स्पोर्टबैक 55 ई-ट्रॉन, ई-ट्रॉन जीटी और आरएस ई-ट्रॉन जीटी आदि शामिल हैं।

कंपनी महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित अपने विनिर्माण संयंत्र में क्यू3, क्यू3 स्पोर्टबैक, क्यू5, क्यू7, ए4 और ए6 जैसे पेट्रोल मॉडल असेंबल करती है। एक साक्षात्कार के दौरान ऑडी इंडिया के प्रमुख बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा कि ईवी का स्थानीय विनिर्माण शुरू करने पर काम चल रहा है और कंपनी के वैश्विक मुख्यालय के साथ सक्रिय चर्चा चल रही है।

उन्होंने कहा, ₹हम ऑडी एजी के साथ बहुत सकारात्मक रूप से काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि किसी समय हम ईवी मॉडलों की स्थानीय असेंबली की घोषणा कर सकेंगे।₹ प्रक्रिया शुरू होने के संभावित समय के बारे में पूछे जाने पर ढिल्लों ने कोई विशेष तारीख नहीं बताई, लेकिन कहा कि भारतीय टीम वैश्विक मुख्यालय के साथ इस मुद्दे पर बहुत सक्रियता से चर्चा कर रही है।

XUV.es और XUV.e9 टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट, साल 2025 के शुरुआत में होंगी लॉन्च

परिवहन विशेष न्यूज

महिंद्रा की आगामी इलेक्ट्रिक गाड़ियां XUV.es और XUV.e9 को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। यह दोनों ही इलेक्ट्रिक SUV रहने वाली है। महिंद्रा की इलेक्ट्रिक एसयूवी को बेहतर परफॉरमेंस देने के लिए भी डिजाइन किया गया है। इतना ही नहीं इन दोनों को ही L2+ ऑटोनॉमस ड्राइविंग और ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स से लैस होंगी। आइए जानते हैं इसके बारे में।

नई दिल्ली। महिंद्रा अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी की रेंज तैयार कर रही है। महिंद्रा की इलेक्ट्रिक गाड़ियां साल 2025 में लॉन्च हो सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हाल ही में कई बार महिंद्रा की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इस बार महिंद्रा XUV700 इलेक्ट्रिक एसयूवी (XUV.es) और कूप (XUV.e9) को एक साथ रोड टेस्ट के दौरान स्पॉट किया गया है।

अगले साल हो सकती है लॉन्च

उम्मीद की जा रही है कि अगले साल महिंद्रा की सबसे पहले XUV.es को लॉन्च किया जाएगा। यह XUV700 का इलेक्ट्रिक वेरिएंट है। इसे पूरी तरह से नए INGLO प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होने वाली है। यह नए इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है, जो परफॉरमेंस, सेफ्टी, टेक्नोलॉजी और आराम के मामले में काफी शानदार रहने वाली है।

डिजाइन ICE से काफी सिमिलर

अपने कूप प्रोफाइल के साथ XUV.es ज्यादा आकर्षक लगती है। इसके डिजाइन में कुछ समानताएं हैं, जैसे कि क्लोज ग्रिल और ट्राइएंगल हेडलैम्प हाउसिंग। इसके LED DRL में कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन कुल मिलाकर लुक और फील काफी हद तक एक जैसा ही होगा। इसका बंपर पहले के जैसा होगा।

रियर डोर हैंडल C-पिलन पर बेस्ड

XUV.es में लोगो को बंद ग्रिल पर रखा गया है, जबकि XUV.e9 में लोगो को बोनट पर देखने के लिए मिला। दोनों SUV में एयरोडायनामिक रूप से डिजाइन किया गया है। इसमें नए एलॉय व्हील हैं, जो लो-ड्रैग टायर के साथ देखने के लिए मिला है। XUV.e9 में पॉलीगोनल आकार के किनारे दिए गए हैं। दोनों UV में बॉडी क्लैडिंग की गई है, लेकिन XUV.9 में बॉडी क्लैडिंग ज्यादा चौड़ी और ज्यादा मजबूत देखने में लग रही है। इसके XUV.e9 के रियर डोर हैंडल C-पिलन पर बेस्ड है।

इन फीचर्स से लैस होंगी गाड़ियां

इन दोनों गाड़ियों में L2+ ऑटोनॉमस ड्राइविंग और ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। इसके साथ ही कनेक्टिविटी के फीचर्स के साथ एक व्यापक रेंज तक पहुंच सकेंगे। इतना ही नहीं यह XUV.es और XUV.e9 के साथ RWD और ऑल-व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शन के साथ उपलब्ध होने की संभावना है। इनकी बैटरी की कैपेसिटी 80 kWh हो सकती है, जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएंगी।

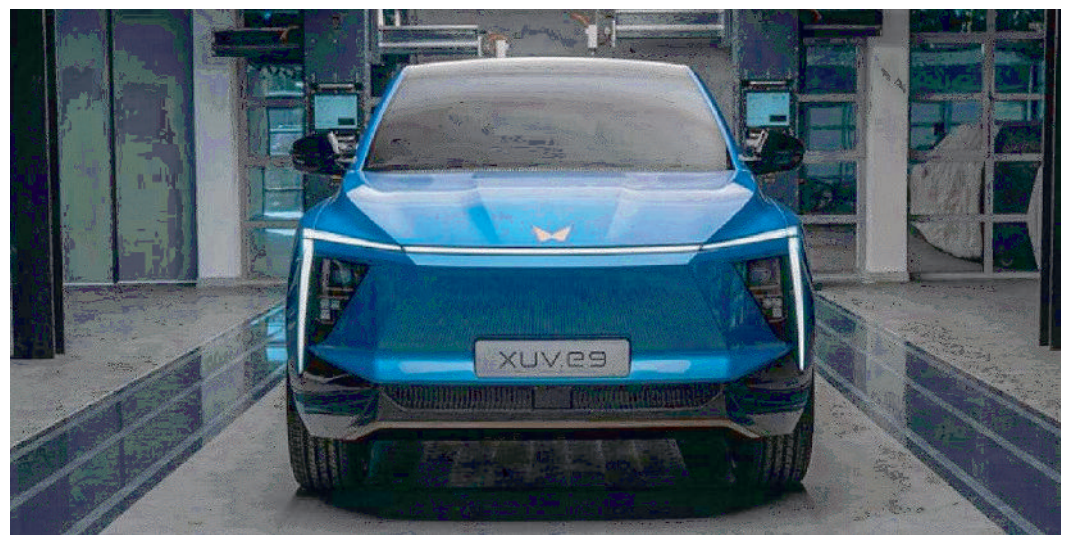

वायनाड त्रासदी में छुपा सच

डा. ओपी जोशी

इस पैनल ने अगस्त 2011 तक अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंप दी थी, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय ने लंबे समय तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और न ही इसे सार्वजनिक चर्चा के लिए जारी किया। प्रोफेसर गाडगिल ने अपनी रिपोर्ट में पश्चिमी घाट के 164280 हेक्टेयर इलाके को पूरी तरह प्रतिबंधित करने के अलावा विकास के नाम पर की जाने वाली विनाशकारी गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने की अनुशंसा की थी।

इस पैनल ने अगस्त 2011 तक अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंप दी थी, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय ने लंबे समय तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और न ही इसे सार्वजनिक चर्चा के लिए जारी किया। प्रोफेसर गाडगिल ने अपनी रिपोर्ट में पश्चिमी घाट के 164280 हेक्टेयर इलाके को पूरी तरह प्रतिबंधित करने के अलावा विकास के नाम पर की जाने वाली विनाशकारी गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने की अनुशंसा की थी। गाडगिल समिति पर लीपापोती करने की गरज से सरकार ने अगस्त 2012 में इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन प्रमुख प्रोफेसर के. कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में एक और समिति का गठन कर दिया। यह समिति दरअसल एक उच्च स्तरीय कार्यसमूह था जिसका काम गाडगिल समिति की रिपोर्ट की समग्र और बहु विषयक तरीके से जांच करना था

केरल का वायनाड हो या उत्तराखंड का जोशीमठ, सभी ने पिछले कुछ सालों में भीषण त्रासदियों को भुगता है। विडंबना यह है कि ये त्रासदियां विकास के अंधे राजनेताओं, नीति-निर्माताओं और बिल्डर-ठेकेदारों के कॉकस की पहल पर बाकायदा जानते-बूझते रची जा रही हैं। देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, समाजशास्त्री, कानूनविद, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट सरीखी सर्वोच्च अदालत ने भी विकास की मौजूदा हवस के खिलाफ अपनी-अपनी तरह से आवाज उठाई है, लेकिन 'विकास यात्रा' बदस्तूर जारी है। इस आलेख में इसी विषय को खंगालने की कोशिश करेंगे। केरल के वायनाड में 30 जुलाई की रात्रि भूस्खलन से हुई त्रासदी के बाद राज्य सरकार ने एक अगस्त को जारी एक आदेश तुरंत वापस ले लिया। आदेश में कहा गया था कि वैज्ञानिक इस त्रासदी के संदर्भ में अपनी राय सार्वजनिक नहीं करें एवं अपने तक ही सीमित रखें। साथ ही वैज्ञानिक इस बाबत कोई अध्ययन करना चाहें तो वे पहले सरकार से अनुमति लें। इस आदेश के पीछे राज्य सरकार का भय प्रतीत होता है। शायद पहले किसी वैज्ञानिक ने इस त्रासदी के बारे में कोई चेतावनी या सलाह दी होगी जिसे अनदेखा किया गया होगा। इस हरकत से सरकार कटघरे में तो आ ही जाती है। वायनाड पहाड़ी जिला है एवं पश्चिमी घाट का हिस्सा है। पश्चिमी घाट की 1400 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला केरल समेत छह राज्यों से गुजरती है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है।

विश्व के आठ सर्वाधिक जैव-विविधता वाले स्थानों (हॉट स्पाट्स) में एक पश्चिमी घाट भी है। पश्चिमी घाट के पर्यावरण को लेकर सरकार ने पहले भारतीय विज्ञान संस्थान (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेगलुरु) में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र के संस्थापक प्रोफेसर माधव गाडगिल की अध्यक्षता में 'पश्चिमी घाट पारिस्थितिक विशेषज्ञ पैनल' (डब्ल्यूजीईईपी) गठित किया था। इस पैनल ने अगस्त 2011 तक अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंप दी थी, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय ने लंबे समय तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और न ही इसे सार्वजनिक चर्चा के लिए जारी किया। प्रोफेसर गाडगिल ने अपनी रिपोर्ट में पश्चिमी घाट के 164280 हेक्टेयर इलाके को पूरी तरह प्रतिबंधित करने के अलावा विकास के नाम पर की जाने वाली विनाशकारी गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने की अनुशंसा की थी। गाडगिल समिति पर लीपापोती करने की गरज से सरकार ने अगस्त 2012 में इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन प्रमुख प्रोफेसर के. कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में एक और समिति का गठन कर दिया। यह समिति दरअसल एक उच्च स्तरीय कार्यसमूह था जिसका काम गाडगिल समिति की रिपोर्ट की समग्र और बहु विषयक तरीके से जांच करना था। इस समिति ने 60000 हेक्टेयर क्षेत्र को पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र (इकोलाजिकली सेंसिटिव जोन) बनाने का सुझाव दिया था। दोनों ही समितियों के सुझावों पर ध्यान नहीं देकर केन्द्र सरकार ने सम्बन्धित राज्य सरकारों को संवेदनशील क्षेत्रों में बड़े उद्योग एवं व्यापक खनन कार्य को छोडक़र व्यावसायिक एवं विकास गतिविधियां करने की अनुशंसा की। पर्यावरण की परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखकर की गई गतिविधियों से इस पर्वतमाला के कई भाग उजाड़ एवं जर्जर हो गए। वायनाड के संदर्भ में पढने में आया कि यहां जिस क्षेत्र में भूस्खलन हुआ, वहां कुछ वर्षों पहले बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए थे। वर्ष 2022 के एक अध्ययन में बताया गया कि वर्ष 1950 से लेकर 2020 के मध्य तक वायनाड जिले में 62 प्रतिशत वन क्षेत्र समाप्त हो गया था।

वायनाड की ढीली मिट्टी, पेड़ों की कटाई एवं जलवायु बदलाव से कम समय में आयी तेज बारिश से चौरल पर्वत पर तीन बार भूस्खलन हुआ जिससे चोलियार नदी के जलागम क्षेत्र (केचमेंट एरिया) में बसे चार गांव मलबे में दब गए। केरल विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2018 से राज्य में तेज बारिश से भूस्खलन के क्षेत्र 3.46 प्रतिशत बढ़े हैं। केन्द्र के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार पिछले सात वर्षों में आए 3782 भूस्खलन में 59.2 प्रतिशत दर्ज किए गए हैं। इम्पीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की शोधकर्ता मरियम जकारिया का कहना है कि जलवायु बदलाव के कारण वायनाड में वर्षा का पैटर्न बदलने से भूस्खलन का खतरा बढ़ा है। भारतीय ऊष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्था, पुणे के जलवायु विशेषज्ञ आरएम कौल का कहना है कि केरल का आधा हिस्सा पहाडियों तथा पर्वत क्षेत्र से घिरा है, जहां ढलान 20 डिग्री से ज्यादा है जिससे भारी बारिश में भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। वायनाड त्रासदी जलवायु बदलाव से पैदा बारिश के पैटर्न में परिवर्तन के साथ-साथ समय-समय पर वैज्ञानिकों की चेतावनी एवं विशेषज्ञ समितियों की रिपोर्ट नहीं मानने का एक सामूहिक मिला-जुला परिणाम है। केदारनाथ, चमोली, जोशीमठ एवं सिक्किम आदि त्रासदियों के पीछे भी यही कारण है।

वर्ष 1976 की मिश्रा समिति की रिपोर्ट से लेकर 2012 तक जोशीमठ पर पांच वैज्ञानिक रिपोर्टें आयी थीं जिनमें धंसाव के कारण एवं बचाव के उपाय बताए गए थे, परंतु किसी पर भी ध्यान नहीं दिया गया। जलवायु बदलाव के वर्तमान समय में इस प्रकार की त्रासदियों से बचने के लिए जरूरी है- केन्द्र व राज्य सरकारें विषय विशेषज्ञों की सलाहों को महत्व दें। सामान्यतः सरकारें इनसे इसलिए कतराती हैं कि वे कई बार सरकार की नीतियों के विरोध में होते हैं। आमतौर पर सत्ता तंत्र हमेशा विशेषज्ञों से बेरुखी रखकर अपने सेवानिवृत्त या कार्यरत अधिकारियों, ठेकेदारों एवं भवन निर्माताओं की सलाहों को ज्यादा महत्व देता है। विशेषज्ञों को महत्व देकर कुछ कार्य पिछली सरकारों ने किए थे जो निश्चय ही प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय हैं। वायनाड त्रासदी से सबक लेकर मौजूदा सरकारें भी विषय विशेषज्ञों की बातों को महत्व देना शुरू करें तो बेहतर होगा। जब तक हम अंधाधुंध विकास का लालच नहीं छोड़ पाएंगे, तब तक इस तरह के विनाश को रोकना संभव नहीं है। अभी भी समय है कि हम प्रकृति का संरक्षण करना शुरू कर दें। इसके निश्चित ही फलदायी परिणाम आएंगे। कुछ प्रदेशों में वृक्षों का अंधाधुंध कटान हो रहा है। इस कटान को रोकने के लिए सख्त कानून तो बने हैं, लेकिन उनके क्रियान्वयन में हम चूक कर जाते हैं। तभी तो इस तरह की त्रासदियां आम होने लगी हैं। कानून का सही क्रियान्वयन तथा समाज को सचेत करना जरूरी है।

संपादक की कलम से

तनख्वाह की गोटियां

सवाल तनख्वाह से शुरू होकर इसी पर खत्म हो रहा है। जिस तनख्वाह में ओपीएस जोडक़र कांग्रेस सरकार बनी, उसी की बदौलत मंत्री और सीपीएस को दो महीने का वेतन विलंबित लेना पड़ रहा है, लेकिन तस्वीर यहां मुकम्मल नहीं होती। तनख्वाह तुरंत न लेने का फैसला सांकेतिक तौर पर बता रहा है कि खजाने ने बोझ उठाना मना कर दिया या यह कि अब सरकार अपने चरित्र से अपव्ययता के निशान हटा देगी। कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार एवं कैबिनेट रैंक प्राप्त गोकुल बुटेल ने अपनी तनख्वाह की 'गोटी' छोड़ दी। इस तरह वह सरकारी खजाने के सामने 'व्हिसिल ब्लोअर' की तरह प्रकाश में आ गए। मसला तनख्वाह छुड़वाने का ही होता तो कई उपाय हो सकते हैं, लेकिन यहां फिजूलखर्चियों के दामन में आग लगी है और झुलसने की ताकीद में लक्षण उभर रहे हैं। एक ओर केंद्र से असहयोग की परिपाटी में तू तू-मैं मैं से घिसटती आर्थिकी और ऊपर से गुरबत में गुलकंद बांटने की प्रथा ने हिमाचल में केंचुली फंसा दी है। तीन दिन पहले देश के प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी के बाद 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने के लिए 28602 करोड़ का ऐलान करते हुए हिमाचल को धत्ता बताते हैं। हमारे पड़ोस और पर्वतीय प्रदेश उत्तराखंड तथा पंजाब को इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी मिल रहे हैं, लेकिन केंद्र में चारों सांसद भेजने वाले हिमाचल को ऐसी बहार नहीं मिली। कहना न होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने औद्योगिक पैकेज देकर हिमाचल को औद्योगिक क्षेत्र में चलना सिखाया था, लेकिन मोदी सरकार अब घुटनों पर ला रही है। आश्चर्य यह कि कांग्रेस से एक सांसद छीन कर भाजपा ले गई और चुनावी पलकों से भी कांग्रेस की हिम्मत छीन ली, फिर भी कसूरवार हिमाचल को बनाया जा रहा है।

पर्वतीय अस्मिता के भूगोल में फंसा अर्थशास्त्र अपनी जान कैसे बचाएगा। ऐसे में अनुराग ठाकुर से पूछें या जगत प्रकाश नड्डा के प्रकाश में चंद किरणें वसूलें, लेकिन हकीकत यह है कि हिमाचल की केंद्र में वकालत रुक गई है या शिमला में सरकार की मशीनरी हिल गई है। बहरहाल सियासत के दोनों पाट दोषी हैं या सारा डिस्कोर्स ही बदले ले रहा है। विधानसभा की कार्यवाहियों में होते संग्राम और शिमला से दरकिनार होती प्रदेश की आवाज को आखिर सुनेगा कौन। इसीलिए आज तक न शासन, न प्रशासन, और न ही आर्थिक व्यवस्था के आदर्श बने। हमें मंडी में मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए कार्यालय चाहिए, तो नए विकास की कहानी पर चप्पा चप्पा चल रहे देहरा को सत्ता की निशानी चाहिए। सूखे होंगे बरगद के पेड़ जहां खजाना रखा था, हमने तो बाढ़ में डूबकर प्यास बुझानी सीख ली। हिमाचल में सियासी प्यास और सत्ता के पियाऊ जहां तहां दिखाई देते हैं, वहां हर सरकार के जुर्म में आर्थिक हंडियों ने इज्जत गंवाई है। एक कमजोर-आर्थिक संसाधनविहीन राज्य की मिलकीयत में आर्थिक खुशहाली छीनते वर्गों के बीच असहाय निजी क्षेत्र, वहां उपलब्ध नौकरियां और बेरोजगार होते युवाओं के लिए क्या मंत्री व सीपीएस की घोषणाएं कभी बोलती हैं या कुछ सोचकर तौलती हैं। हम अंधेरे में सोने की खान ढूंढ रहे हैं। हमें ताज पहनने की आदत है, इसलिए कुछ अंधे-बहरे स्कूल-कालेज, संवेदनहीन चिकित्सालय और घाटे के बजट को झूठा ठहराने के लिए नए-नए कार्यालय खोल दिए जाएंगे। मानसून सत्र में दोनों पक्ष शपथ लेकर आर्थिक संवाद कर लें, ताकि पता चले कि जहां मुर्गियां हलाल हुईं, वहां खून क्यों इनसान का बहा।

कविता

झूठ ही परम सत्य है'

नेताजी अपने मित्रों की कैबिनेट में बता रहे थे कि घोर कलियुग चल रहा है और इस कलियुग में झूठ ही परम सत्य है। बाकी सब मिथ्या है। सौ बार बोला गया झूठ अंततः सच में तब्दील हो जाता है। यही झूठ की सबसे बड़ी ताकत है। नेताजी बता रहे थे कि झूठ बोलने से सत्ता मिलती है और सत्ता मिलने पर कुर्सी मिलती है। कुर्सी में बड़ी ताकत होती है और यह ताकत झूठ की आत्मा से निकल कर आती है। इसलिए झूठ को परम सत्य माना जाना चाहिए। यह हमारा सिद्धांत होना चाहिए और इस सिद्धांत पर मरते दम तक अमल भी होना चाहिए। नेताजी उपदेशक की मुद्रा में बता रहे थे कि यह जग झूठा है। मरते समय कोई किसी के साथ नहीं जाता। नोटों से भरे ब्रीफकेस अलमारियों में ही रह जाते हैं। अवैध कब्जे धरती पर ही रह जाते हैं। धोखाधड़ी और हेराफेरी से जो माल इक_ा किया होता है, वह सब यहीं रह जाता है। पत्नी की आंखों में धूल झोंक कर जो प्रेमिकाएं दाएं-बाएं बनाई होती हैं, वे भी हमारी आत्मा के साथ स्वर्ग या नरक नहीं जाती, बल्कि धरती पर रह जाती हैं और फिर अन्य पुण्य आत्माओं की प्रेमिकाएं बन जाती हैं। इसलिए झूठ को आंच नहीं आने देनी चाहिए। सत्य को तो कभी भी पराजित किया जा सकता है। सत्य बोलने वालों के हजारों दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन झूठ बोलने वालों के करोड़ों फॉलोअर होते हैं। जो जितना झूठा, उतना ही महान। महानता आसानी से हासिल नहीं होती। लगातार पब्लिक के बीच झूठ बोलना पड़ता है। झूठी गारंटियां देनी होती हैं। झूठे वादे करने होते हैं। झूठे आश्वासन देने होते हैं। बार-बार झूठ को दोहराना पड़ता है। फिर पब्लिक फिदा हो जाती है। पब्लिक अपनी खुशी फिर हम पर वोट कुर्बान करके जाहिर करती है। हमारे गले में नोटों की माला भी पहनाती है। हमें वोट और नोट दोनों मिलते हैं। झूठ का पूरा डंका बजता है। सत्य को कोई नहीं पूछता। झूठ वाले का राजनीति में पूरा जलवा रहता है।

राजनीति में जिसका जलवा और बोलबाला है, वही जनप्रिय नेता कहलाता है। वह हारने के बाद भी जीतता है। वह यह साबित कर देता है कि झूठ को बार-बार पराजित नहीं किया जा सकता। झूठ तो जीतेगा ही और जीत के बाद ओहदा भी पाएगा। नेताजी मित्रों की बैठक में धाराप्रवाह बता रहे होते हैं और मित्र उनकी हर बात पर ताली बजाकर अपनी सहमति जताते हैं। यह मित्र नेताजी के उन दिनों के सखा हैं, जब नेताजी ने नया-नया झूठ बोलना सीखा होता था और फिर लगातार झूठ बोलने में वह एक के बाद एक कीर्तिमान स्थापित करते चले गए थे। नेताजी बता रहे थे कि हमने लाखों युवाओं को रोजगार नहीं दिया। फिर भी हमें सत्ता मिल गई। यह सब झूठ का जलवा है। हमने महिलाओं को भी सब्जबाग दिखाए। महिलाएं हमारे झांसे में आ गईं। यह भी झूठ का सबसे बड़ा जलवा है। इसके लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। इसलिए मित्रो अपने-अपने हलके में जाकर झूठी घोषणाएं करते रहो। इससे पब्लिक का उत्साहवर्धन होता है। पब्लिक को पता चलता रहता है कि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि निठल्ले नहीं बैठे, बल्कि लगातार हमारे हित में कुछ न कुछ करते जा रहे हैं। इससे हमें कर्मठ और गतिशील होने का तमगा मिलेगा। गति झूठ बोलने से ही आती है। जिसने जिंदगी में झूठ नहीं बोला, उसकी मरकर भी गति नहीं होती। स्वर्ग और नरक कहीं पर भी एंट्री नहीं मिलती। ऐसा नेताजी अपने मित्रों को समझा रहे हैं। नेताजी की बैठक जारी है और झूठ को लेकर व्याख्यान भी चला हुआ है।

कुलभूषण उपमन्यु

अहिंसक विश्व समाज कैसे बने?

गांधी जी का आत्मनिर्भर समाज का सिद्धांत इस दृष्टि से उपयोगी हो सकता है, यदि इसे वैश्विक स्तर पर भी लागू किया जा सके। जब सभी देश आत्मनिर्भर होने के लक्ष्य से काम करेंगे तो अनंत साधन और शक्ति हथियाने की जरूरत समाप्त हो जाएगी। व्यापारिक मंडियों पर कब्जे की जरूरत ही नहीं रहेगी। अंतरराष्ट्रीय हिंसा का बड़ा कारण सीमाओं की रक्षा भी है। जैसे आर्थिक विस्तारवाद खराब है, वैसे ही सीमाई विस्तारवाद भी है। इसके लिए सशक्त विश्व मंच की जरूरत है जो सीमाओं के संरक्षण की गारंटी दे'

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। विकसित बुद्धि, भाषा के विकास, सीधे खड़े होने की सामथ्र्य और उंगलियों की विशिष्ट बनावट के चलते ही मनुष्य अन्य पशु समुदाय से अधिक विकसित हो सका है। अन्यथा बहुत सी पशु वृत्तियां मनुष्य में भी विद्यमान हैं। हर मनुष्य और मनुष्य समाज सुख-शांति से रहना चाहता है। तमाम भौतिक सुख-सुविधाएं पैदा करने के बावजूद पशु वृत्तियों के चलते हिंसक और लालची व्यवहार के कारण मनुष्य एक-दूसरे को कष्ट पहुंचा कर दुखी करता आया है। इसी के कारण स्वयं भी दुखी होता आया है। शायद इसी पशुवृत्ति जनित दुःख निवारण के लिए धर्मों का आविष्कार मनुष्य समाज ने किया होगा, जिसमें कुछ आत्म नियमन के द्वारा पशु वृत्तियों के दमन की अपेक्षा करके समाज को सुखी बनाने की चेष्टा की गई है। किन्तु पशु वृत्तियां धर्मों पर भी हावी हो गईं। धीरे धीरे यह विचार आने लगे कि मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है। इसलिए दूसरे के धर्म को निकृष्ट बता कर उसे समाप्त या नियंत्रित करने के प्रयास शुरू हो गए। इससे एक नए प्रकार की भयानक हिंसा का जन्म हो गया। 'चले थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास' कहावत को चरितार्थ करते हुए सुख और शांति की दिशा में बढने के नाम पर बड़ी हिंसा का शिकार हो गए।

कबीलाई समाज के समय जब मनुष्य समाज उतना विकसित नहीं था, तब हिंसा छोटे स्तर पर छोटी छोटी बातों पर होती थी। खाना तलाशने, शिकार के इलाके पर आधिपत्य जमाने के लिए एक कबीला दूसरे से टकरा जाता था। जैसे जैसे मनुष्य विकसित होता गया, वैसे वैसे उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गईं। फिर टकराव के मौके भी बढ़ते गए। टकराव के शस्त्रास्त्र भी बढ़ते गए। यानी सुख-शांति से जीने के हालात कम होते चले गए। पहले लाठी डंडों से झगड़े निपट जाते थे, फिर भाले, तीर, तलवारों की नौबत आ गई, और अब महा विनाशक अणु बमों के खतरे में जीने को अभिशप्त हैं। दर्द बढ़ता ही गया, ज्यों ज्यों दवा की, यह कहावत चरितार्थ होने लगी। अनेक धर्मों, पंथों ने साधना और धार्मिक नियमन से व्यक्तिगत तौर पर अहिंसक व्यवहार में पारंगत महा मानवों को पैदा किया। किन्तु सामूहिक स्तर पर अहिंसा का प्रयोग बहुत नगण्य ही रहा, जिसमें शायद महात्मा गांधी एक अपवाद हैं जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसा को एक उपकरण की तरह उपयोग करने का साहस किया। बड़े पैमाने पर सफलता भी हासिल की। किन्तु उसमें भी बहुत से लोग इस उपकरण को मान्यता देने में संकोच करते हैं और इस बहस में फंसे रहते हैं कि आजादी अहिंसक आंदोलन से मिली या क्रांतिकारी आंदोलन और नेता जी सुभाष चंद्र बोस के सैनिक प्रयास से। हालांकि यहां मकसद यह तय करना नहीं है कि किसके प्रयास से आजादी मिली, सबके ही प्रयास महत्वपूर्ण रहे हैं, किन्तु मूल प्रश्न है कि अहिंसा के उपकरण को व्यक्तिगत स्तर से आगे बढ़ कर सामूहिक स्तर तक उपयोगी कैसे बनाया जाए, ताकि अंतरराष्ट्रीय मामलों को सुलझाने के लिए युद्धों के अलावा अहिंसक उपाय किए जा सकें और सुख-शांतिपूर्ण जीवन संभव हो सके। इस दिशा में यह भी देखा जाना चाहिए कि देशों में युद्धों के मुख्य कारण क्या रहे हैं।

इतिहास के अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि बहुत से संघर्ष आर्थिक प्रभुत्व के लिए हुए हैं या फिर अपनी धार्मिक विचारधाराओं के जबरदस्ती प्रचार की भूख के कारण हुए हैं। कोई यह बोले कि मेरे रास्ते से स्वर्ग या जन्नत मिलना तय है, तो भाई आप स्वर्ग या जन्नत के मजे लूट लो, दूसरे को क्यों परेशान करते हो कि आप भी मेरे रास्ते चलो। जिस धर्म का उद्भव या विकास मानव समाज को सुखी करने के लिए हुआ था, उसी के कारण दुनिया में कितना हिंसक वातावरण बना है, और सब तरफ दुःख ही फैलने का कारण बन गया है। इस तरह के हालात में अहिंसक शक्ति को कैसे सर्वोपरि बनाया जा सकता है, वरना हिंसा और प्रति हिंसा के दुश्चक्र में धर्म तो गायब ही हो जाता है। जो मनुष्य समाज दूसरे को दुखी करेगा, वह स्वयं भी दुखी होगा ही, क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया तो प्रकृति का नियम ही है। इतनी बात समझ आ जाए तो आगे का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। आर्थिक कारणों से होने वाली हिंसा भी दो तरह की है। एक तो अभाव जनित है। अभाव दूर करके जिसका निराकरण किया जा सकता है। दूसरी है लालच जनित, जिसके बारे में गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति के पास सबकी जरूरतें पूरा करने के लिए पर्याप्त है किन्तु किसी के लालच की पूर्ति के लिए कुछ भी नहीं। यानी लालच प्रकृति की शक्ति पर अनचाहा भार है और समाज में अन्याय का कारण भी। गांधी जी का आत्मनिर्भर समाज का सिद्धांत इस दृष्टि से उपयोगी हो सकता है।

इसे वैश्विक स्तर पर भी लागू किया जा सके, तो यह काफी उपयोगी है। जब सभी देश आत्मनिर्भर होने के लक्ष्य से काम करेंगे तो अनंत साधन और शक्ति हथियाने की जरूरत समाप्त हो जाएगी। व्यापारिक मंडियों पर कब्जे की जरूरत ही नहीं रहेगी। अंतरराष्ट्रीय हिंसा का बड़ा कारण सीमाओं की रक्षा भी है। जैसे आर्थिक विस्तारवाद खराब है, वैसे ही सीमाई विस्तारवाद भी है। इसके लिए सशक्त विश्व मंच की जरूरत है जो सीमाओं के संरक्षण की गारंटी दे सके। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ उस दिशा में विकसित किया जा सकता है? यदि सीमाओं की सुरक्षा सलाह मशविरे से संभव हो जाए तो हिंसा का बड़ा कारण समाप्त हो जाएगा। फिर आप सेनाओं और भयंकर शस्त्रास्त्रों पर खर्च राशि को बहुत घटा सकते हैं और समाज की सुख-समृद्धि पर खर्च कर सकते हो। काश! ऐसा हो पाए'। पूरे विश्व को निशस्त्रीकरण की तरफ बढना चाहिए, तभी शांति आएगी।

'जमानत' संवैधानिक नियम

सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश कई संदर्भों में यह टिप्पणी करते रहे हैं कि न्यायिक सिद्धांत में जेल 'अपवाद' है और जमानत 'नियम' है। धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में भी यह सिद्धांत लागू होता है। निचली अदालतों को भी यह ध्यान में रखना चाहिए और जमानत देने में संकोच नहीं करना चाहिए। सर्वोच्च अदालत की न्यायिक पीठ ने 'प्रेम प्रकाश बनाम प्रवर्तन निदेशालय' के मामले में आरोपित को जमानत दी है। मामला धनशोधन का ही था। गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति घोटाले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 'भारत राष्ट्र समिति' की नेता के. कविता को भी सर्वोच्च अदालत ने जमानत पर रिहा किया है। हालांकि सिसोदिया को करीब डेढ़ साल और कविता को पांच महीने जेल में काटने पड़े हैं, जबकि दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसी केस में जेल में अब भी बंद हैं। मामले का औपचारिक ट्रायल अभी शुरू नहीं हो पाया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी जांच पूरी कर आरोप-पत्र अदालत में दाखिल कर दिए हैं, जबकि सीबीआई जांच अभी जारी है। 'जेल-जमानत' वाले न्यायिक सिद्धांत के पीछे सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश औसतन व्यक्ति की मुक्ति के मौलिक और संवैधानिक अधिकार की दलील देते रहे हैं कि महज जांच और पूछताछ के लिए व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में बंद रखना गैर-न्यायिक है। जमानत का प्रावधान भी संवैधानिक नियम है। 'जेल बनाम जमानत' वाले सिद्धांत पर उन दो न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया है, जो भारत के प्रधान न्यायाधीश बनने की कतार में हैं। बीते कुछ समय से 'जमानत' को लेकर सर्वोच्च अदालत की मानसिकता और सोच में बदलाव आया है। यकीनन यह स्वागत-योग्य निर्णय है, क्योंकि मानवीय है। यह बदलाव अपेक्षित और कालातीत भी था और कई मंचों पर विमर्श के जरिए मांग की जा रही थी कि जमानत की प्राथमिकता होनी चाहिए। एक अहम कारण यह भी रहा है कि देश में जितनी जेलें हैं और उनमें कैदियों की क्षमता है, उनसे अधिक कैदियों को जेल में बंद किया जा रहा है।

हिरासत वाले आरोपितों को भी जेल में कैद किया जा रहा है, लिहाजा लगातार अनियमितताएं और विसंगतियां उभर कर सामने आ रही हैं। करीब दो साल पहले 'विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत सरकार' के केस में सर्वोच्च अदालत ने धनशोधन निवारण कानून के अत्यंत कड़े प्रावधानों को 'सही' करार दिया था। राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ सरकार ने ईडी के अतिरिक्त दुरुपयोग को बढ़ा दिया है, ऐसी शिकायतों और दलीलों के मद्देनजर अदालत ने वह फैसला सुनाया था। दुरुपयोग के डर और शिकायतों को खारिज कर दिया गया था, लिहाजा वह न्यायिक फैसला आज भी 'देश का कानून' है। जिस सिद्धांत की आज चर्चा की जा रही है, उसके बिल्कुल विरोधाभास में यह कानूनी फैसला है। फिर भी शीर्ष अदालत के स्तर पर ही व्याख्याएं और कोशिशें की जा रही हैं कि जेल पर जमानत को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जुलाई में शराब घोटाले के संदर्भ में ही केजरीवाल को जमानत देते हुए सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीशों ने ईडी की व्यापक शक्तियों पर सवाल उठाए थे, जिनके तहत एजेंसी गिरफ्तारियां करती रही है। जमानत के बावजूद केजरीवाल सीबीआई केस में जेल में बंद हैं। हालांकि वह केस भी बड़ी न्यायिक पीठ को सौंप दिया गया है, लेकिन अदालत की पीठ ने टिप्पणियां की थी कि ईडी अपने आप में ही विश्वास कर लेती है और उसी आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर लेती है।

व्यक्ति को आरोपी मान लेती है। किसी को भी गिरफ्तार करने से पूर्व लिखित में देना चाहिए कि एजेंसी फलां आधार पर आपको गिरफ्तार करना चाहती है। उस लिखित रिकॉर्ड के आधार पर आरोपित अदालत में उस कथित अवैध गिरफ्तारी को चुनौती दे सकता है। कानून में ये बचाव जरूरी हैं, क्योंकि धनशोधन मामले में जमानत लेना लगभग असंभव बना दिया गया है। जमानत के हालिया मामलों में न्यायाधीशों ने कानून की संकीर्णता से उठकर फैसले सुनाए हैं। ये भी बहुत चुनौतीपूर्ण काम हैं। कुछ संदर्भों में सर्वोच्च अदालत ने यह नियम स्थापित कर दिया है कि यदि आरोपित ने अपराध की अधिकतम अवधि का आधा समय भी जेल में काट लिया है, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए। बहरहाल जेल बनाम जमानत की यह प्रक्रिया शुरू हुई है, तो उस पर संसद में विचार होना चाहिए, ताकि अंतिम कानून बनाया जा सके। कानून बनाते समय सभी संबद्ध पक्षों के साथ विचार-विनिमय होना चाहिए, ताकि कानून बनने के बाद किसी को कोई आपत्ति न रहे।

विस्तारा-एयर इंडिया मर्जर से टाटा ग्रुप का बढ़ेगा दबदबा, इंडिगो की बढ़ेगी टेंशन

परिवहन विशेष न्यूज

सरकार ने टाटा ग्रुप की एयर इंडिया और विस्तारा के बीच मर्जर को मंजूरी दे दी है। दरअसल सिंगापुर एयरलाइंस को एयर इंडिया के साथ विस्तारा के प्रस्तावित मर्जर के हिस्से के रूप में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) के लिए सरकार से मंजूरी मिल गई। विस्तारा का संचालन टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस मिलकर करते हैं। मर्जर इस साल के आखिर तक पूरा हो सकता है।

नई दिल्ली। टाटा ग्रुप की एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर पर सरकार ने अपनी मुहर लगा दी। अब 11 नवंबर को विस्तारा की आखिरी फ्लाइट उड़ान भरेगी। इस मर्जर के बाद विस्तारा की सभी फ्लाइट्स का ऑपरेशन एयर इंडिया ही संभालेगी। आइए जानते हैं कि विस्तारा सर्विस कब तक काम करेगी और मर्जर के बाद विस्तारा के कर्मचारियों का क्या होगा।

विस्तारा की बुक उड़ानों का क्या होगा?

आप 3 सितंबर तक विस्तारा की फ्लाइट बुक कर सकते हैं। लेकिन, उड़ान की तारीख 11 नवंबर से बाद की नहीं होगी। इसके बाद विस्तारा की फ्लाइट बुक करने के लिए आपको एयर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। हालांकि, पीएनआर पहले जैसा ही रहेगा। एयर इंडिया के सीईओ के मुताबिक, 2025 की शुरुआत तक विमान विस्तारा के मौजूदा बेड़े से होंगे। इसका मतलब कि शुरुआती दिनों में प्रोडक्ट और सर्विस में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन, धीरे-धीरे एअर इंडिया और विस्तारा के बीच का फर्क धुंधला होता जाएगा।

विस्तारा के लॉयल्टी प्रोग्राम का क्या होगा?

टाटा ग्रुप की दोनों एयरलाइन के मर्जर तक क्लब विस्तारा लॉयल्टी प्रोग्राम जारी रहेगा। फिर यह अकाउंट एयर इंडिया के फ्लाइंग रिटर्न्स प्रोग्राम में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपके पास दोनों एयरलाइन के प्रोग्राम हैं, वे विस्तारा की साइट पर जाकर दोनों को लिंक कर सकते हैं। वहीं, विस्तारा के क्रेडिट कार्ड के बारे में अभी तक कंपन ने कुछ नहीं कहा है। मर्जर के बाद विस्तारा के पूरे स्टाफ और रूट का

भी एअर इंडिया में मर्जर हो जाएगा।

मर्जर से इंडिगो की बढ़ेगी टेंशन

विस्तारा और एयर इंडिया के मर्जर से इंडिगो की टेंशन बढ़ सकती है, जिसका अभी एविएशन मार्केट पर दबदबा है। इंडिगो के पास फिलहाल 61 फीसदी मार्केट शेयर है। वहीं, मर्जर के बाद एयर इंडिया की बाजार हिस्सेदारी 28.7 फीसदी हो जाएगी। अगर टाटा ग्रुप एयर इंडिया के विस्तार के लिए आक्रामक रणनीति अपनाता है, तो उसका नुकसान इंडिगो को उठाना पड़ सकता है। मर्जर के बाद एयर इंडिया में सिंगापुर एयरलाइंस की हिस्सेदारी 25.1 फीसदी रहेगी। वह भी इसमें 3 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इस मर्जर से 396 फ्लीट वाले इंडिगो को तगड़ी चुनौती मिलेगी। एयर इंडिया ने 500 और इंडिगो ने 470 नए प्लेन का ऑर्डर दे रखा है।

विस्तारा का पूरा लेखाजोखा

- विस्तारा ने 13 साल में 6.5 करोड़ लोगों को सर्विस दी।
- एयरलाइन ने जून तक 5 लाख फ्लाइट ऑपरेट की है।
- यह नवंबर तक 50 लाख ग्राहकों को और सर्विस देगी।
- विस्तारा देश में और बाहर 50 जगहों को जोड़ती है।
- विस्तारा के बेड़े में 70 विमान, हर रोज 300 फ्लाइट।

चालू वित्त वर्ष में सरकार को 10.23 लाख रुपये का राजस्व मिला

परिवहन विशेष न्यूज

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरान केंद्र सरकार ने राजस्व के तौर पर मिली राशि का बड़ा हिस्सा 366630 करोड़ रुपये राज्य सरकारों को दिए हैं। मंत्रालय का कहना है इसमें पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 57109 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी रही है। यह सरकार के राजकोषीय संघवाद को दर्शाता है। चालू वित्त वर्ष में जुलाई तक सरकार ने 1300351 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में अप्रैल से जुलाई के दौरान विभिन्न कर और गैर-कर राजस्व के रूप में सरकार को 10,23,406 करोड़ रुपये मिले हैं। वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह बजट अनुमान का 31.9 प्रतिशत के बराबर है। इसमें 7,15,224 करोड़ रुपये कर राजस्व, 3,01,796 करोड़ रुपये गैर-कर राजस्व और 6,386 करोड़ रुपये कर्ज शामिल है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरान केंद्र सरकार ने राजस्व के तौर पर मिली राशि का बड़ा हिस्सा 3,66,630 करोड़ रुपये राज्य सरकारों को दिए हैं। मंत्रालय का कहना है कि इसमें पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 57,109 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी रही है। यह सरकार के राजकोषीय संघवाद को दर्शाता है। चालू वित्त वर्ष में जुलाई तक सरकार ने 13,00,351 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। यह चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान का करीब 27 प्रतिशत है।

इसमें से 10,39,091 करोड़ रुपये राजस्व खाता, जबकि 2,61,260 करोड़ रुपये पूंजीगत खाता व्यय है। इस दौरान सरकार की ओर से 3,27,887 करोड़ रुपये की ब्याज का भुगतान किया गया है, जबकि 1,25,639 करोड़ रुपये प्रमुख सब्सिडी के लिए आवंटित किए गए हैं। सरकार ने जुलाई 2024 तक के मासिक खातों की शुक्रवार को जानकारी दी थी। इससे चालू वित्त वर्ष में सरकार के वित्तीय प्रदर्शन की विस्तृत जानकारी मिली है।

यह वित्तीय रिपोर्ट देश का वित्त का प्रबंधन करने, राजस्व सृजन और आवश्यक व्यय के बीच संतुलन बनाने के साथ राज्य सरकारों को संसाधनों का प्रवाह बनाए रखने के सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालती है।

1 सितंबर से क्रेडिट कार्ड से जुड़ा नियम बदलेंगे एचडीएफसी और आईडीएफसी बैंक, जेब पर होगा सीधा असर

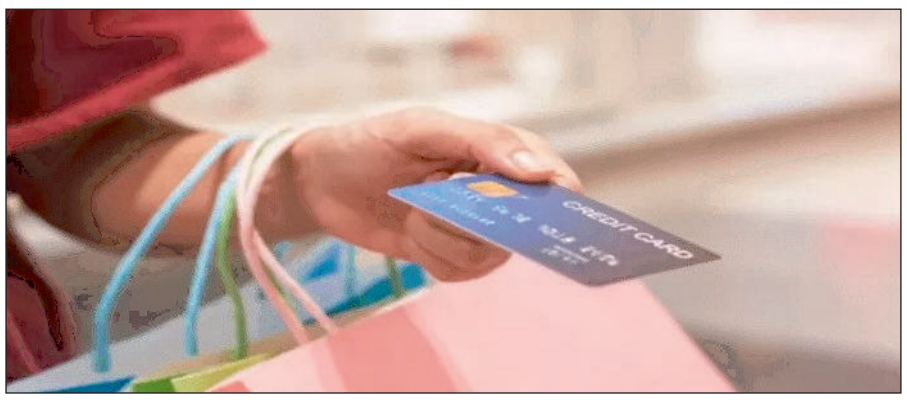

प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक HDFC Bank 1 सितंबर से क्रेडिट कार्ड के नियमों (Credit Card Rule) में बदलाव करने वाला है। बैंक यूटिलिटी ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड प्वाइंट की लिमिट निर्धारित करेगा। साथ ही IDFC First Bank के क्रेडिट कार्ड पर मिनिमम ड्यू अमाउंट कम होने वाला है। RuPay क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट करने पर रिवॉर्ड प्वाइंट भी बदलेगा।

नई दिल्ली। एक सितंबर से कई महत्वपूर्ण वित्तीय बदलाव होने वाले हैं, जिनका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा। ये बदलाव क्रेडिट कार्ड से जुड़े हैं। इसका असर रिवॉर्ड प्वाइंट अर्जित करने और भुनाने पर पड़ेगा। साथ ही, ये भुगतान की समय-सीमा और न्यूनतम शेष राशि को प्रभावित करेंगे।

RuPay क्रेडिट कार्डधारकों को होगा फायदा

1 सितंबर से RuPay क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम में सुधार किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के मुताबिक, अब से RuPay क्रेडिट कार्ड को UPI लेनदेन के लिए भी अन्य भुगतान सेवा प्रदाताओं के समान ही रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। NPCI सर्कुलर ने क्रेडिट कार्ड के उपयोग को बढ़ाने में रिवॉर्ड पॉइंट की अहमियत बढ़ाने पर जोर दिया। उसका कहना है कि RuPay क्रेडिट कार्ड पहले इस मामले में वंचित थे।

एचडीएफसी बैंक में रिवॉर्ड पॉइंट कैप

एचडीएफसी बैंक 1 सितंबर से नए रिवॉर्ड प्वाइंट कैप लागू करेगा। बैंक यूटिलिटी और टेलीकॉम ट्रांजैक्शन से मिलने वाले प्वाइंट की संख्या को हर कैलेंडर महीने में 2,000 तक सीमित कर देगा। इसके अलावा, अब CRED, CheQ और MobiKwik जैसे थर्ड-पार्टी ऐप के जरिए किए गए स्कूल पेमेंट यानी फीस के लिए रिवॉर्ड पॉइंट नहीं दिए जाएँगे।

हालांकि, शैक्षणिक संस्थानों को उनकी वेबसाइट या पॉइंट ऑफ सेल (POS) डिवाइस के जरिए सीधे भुगतान करने पर पॉइंट मिलते रहेंगे। यह पॉलिसी सभी एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के लिए मान्य है, जिसमें स्विगी और टाटा न्यू जैसे को-ब्रांडेड और प्रीमियम कार्ड शामिल हैं।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नए नियम

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड पेमेंट की शर्तें सितंबर 2024 के स्टेटमेंट साइकल से बदल जाएंगी। स्टेटमेंट जेनरेट होने की तारीख से भुगतान की ड्यू डेट से 18 घटाकर 15 दिन कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि कार्डधारकों के पास अपने बिलों का निपटान करने के लिए तीन दिन कम होंगे। साथ ही बैंक ने मिनिमम ड्यू अमाउंट भी घटाया है।

सेल्फ-मेड महिलाओं में जोहो की को-फाउंडर अव्वल, बॉलीवुड एक्ट्रेस का भी जलवा

Hurun India Rich List 2024 में भारतीय महिलाओं ने भी अपना स्थान बनाया है। अगर भारत के टॉप-10 महिला अरबति की बात करें तो सबसे पहला नाम जोहो (Zoho) की को-फाउंडर राधा वेम्बू (Radha Vembu) का आता है। इस लिस्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला (Juhi Chawla) ने भी अपना स्थान बनाया है। इस लेख में टॉप-10 महिला अरबपति के नाम और उनकी नेट वर्थ के बारे में जानते हैं।

नई दिल्ली। इस हफ्ते हुरुन इंडिया (Hurun India) ने भारत रिच लिस्ट 2024 (Hurun India Rich List 2024) जारी कर दी। इस लिस्ट में पुरुषों के साथ महिलाओं को भी स्थान मिला है। बता दें कि यह पहली बार है जब भारत के रिच लिस्ट में 300 से ज्यादा अरबपतियों का नाम शामिल हैं। इस बार लिस्ट में 102 एनआरआई को स्थान दिया गया है।

भारत के अरबपति महिलाओं की बात करें तो सबसे पहला नाम भारत की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी जोहो (Zoho) की को-फाउंडर राधा वेम्बू (Radha Vembu) का आता है। इसके बाद नायका (Nykaa) की CEO फाल्गुनी नायर (Falguni Nayar), अरिस्ता नेटवर्क्स (Arista Networks) की CEO जयश्री उल्लाल (Jayshree Ullal) आदि का नाम भी शामिल हैं।

बता दें कि इस लिस्ट में उन महिलाओं का नाम शामिल हैं जिनके पास कोई पुश्तैनी संपत्ति नहीं हैं। उन्होंने अपने दम पर इतनी संपत्ति कमाई है। आइए, हम आपको इस आर्टिकल में भारत की टॉप-10 महिला अरबपति और उनकी संपत्ति के बारे में बताएंगे।

भारत की टॉप-10 महिला अरबपति (India Top-10 Richest Women)

- इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जोहो कंपनी की को-फाउंडर राधा वेम्बू का है। राधा वेम्बू के पास कुल 47500 करोड़ रुपये की संपत्ति है। फोर्ब्स (Forbes) भारत के अरबपतियों की लिस्ट में राधा वेम्बू 55वें नंबर पर हैं।
- भारतीय महिलाएं अरबपतियों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर ब्यूटी ब्रांड Nykaa की सीईओ फाल्गुनी नायर हैं। इनकी नेट वर्थ 32200 करोड़ रुपये है।
- महिला अरबपतियों की लिस्ट में अरिस्ता नेटवर्क्स (Arista Networks) की अध्यक्ष जयश्री उल्लाल (Jayshree Ullal) का तीसरे स्थान पर हैं। इनके पास 32100 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति है।
- बायोकॉन (Biocon) की फाउंडर किरण मजूमदार शॉ (Kiran Mazumdar-Shaw) के पास 29000 करोड़ रुपये की नेटवर्थ है। वह भारत की टॉप-10 महिला अरबपति की लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं।
- भारत की टॉप-10 महिला अरबपति की लिस्ट में पांचवें पायदान पर नेहा नरखेड़े (Neha Narkhede) हैं। यह अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी कॉनफ्लुएंट (Confluent) की को-फाउंडर हैं। इनकी नेट वर्थ 4900 करोड़ रुपये है।
- इस लिस्ट में छठें नंबर पर बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला (Juhi Chawla) का नाम हैं। वह आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की मालिक है। इस टीम के मालिक शाहरुख खान भी है। जूही चावला की नेटवर्थ 4600 करोड़ रुपये है। भारत रिच लिस्ट 2024 में वह पहली महिला अभिनेत्री हैं।
- पेप्सिको (PepsiCo) की Ceo इंदिरा के नूई (Indra Nooyi) का नाम इस लिस्ट में सातवें नंबर पर हैं। इनके पास 3900 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति है।
- 3100 करोड़ रुपये की नेट वर्थ के साथ लेंसकार्ट (Lenskart) की फाउंडर नेहा बंसल (Neha Bansal) का नाम लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं।
- UV टेक्नोलॉजीस (UV Technologies) की सीईओ देविता राजकुमार सराफ (Devita Saraf) का नाम इस लिस्ट में नौवें स्थान पर हैं। इनके पास कुल 3000 करोड़ रुपये की संपत्ति है।
- कविता सुब्रमण्यम (Kavita Krishnamurti) स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी अपस्टॉक्स (Upstox) की सह-संस्थापक हैं। इनकी नेटवर्थ 2700 करोड़ रुपये है। यह महिला अरबपति की लिस्ट में टॉप-10 पर हैं।

हो जाएं सावधान! हो रहा है नौकरी से लेकर स्टॉक ट्रेडिंग स्कैम, बचने के लिए जरूर अपनाएं ये तरीके

Cyber Fraud वर्तमान में सोशल मीडिया के जरिये फ्रॉड काफी हो रहा है। बैंक अकाउंट से हैक करना या फिर डिस्काउंट का झांसा दिया जा रहा है। साइबर फ्रॉड के मामलों में लगातार तेजी आ रही है। हैकर्स फ्रॉड के लिए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। ऐसे में आपको हम इस आर्टिकल में फ्रॉड के नए तरीकों के साथ उनसे बचने के तरीकों के बारे में बताएंगे।

नई दिल्ली। आज कल साइबर फ्रॉड के मामलों में तेजी देखने को मिला है। मोबाइल फोन, बैंक अकाउंट को हैक करके वैसे भी स्कैम होता ही था। लेकिन, अब ठगी के लिए नए तरीके अपनाएं जा रहे हैं। इन तरीकों से बचना बेहद जरूरी है।

अगर नए स्कैम की बात करें तो अब नौकरी का झांसा देकर भी स्कैम किया जा रहा है। हाल में स्कैम को लेकर एक मामला सामने आया है। इसमें कंज्यूमर के पास इंडियन पोस्ट (Indian Post) की तरफ से मोबाइल पर मैसेज आता है, जिसमें कहा जाता है कि यूजर को बैंक अकाउंट को पैन से लिंक करने के लिए मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। अगर यूजर इस मैसेज के लिंक पर क्लिक नहीं करता है तो उसका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा।

यह फेक मैसेज है। इस मैसेज को लेकर इंडियन पोस्ट ने साफ कहा है कि वह अपने ग्राहक को इस तरह का कोई मैसेज नहीं भेजता है।

अब ऐसे में सवाल आता है कि इस तरह के फर्जीवाड़ा मैसेज से बचने के लिए यूजर को क्या करना चाहिए। कंज्यूमर को साइबर फ्रॉड से बचने के लिए कौन-से तरीकों को अपनाना चाहिए।

WhatsApp पर भी हो रहा फ्रॉड

वॉट्सऐप पर भी कई मैसेज में झूठे जॉब ऑफर्स किया जाता है। इसमें ठग जॉब ऑफर करने के लिए लिंक शेयर करते हैं। कई बार यूजर इन लिंक पर क्लिक कर लेते हैं। लिंक पर क्लिक करते ही ठग यूजर के मोबाइल को हैक करके सारी डिटेल्स को चुरा लेता है।

ऐसे में वॉट्सऐप के इस फ्रॉड से बचने के लिए आपको कभी भी जॉब ऑफर करने वाले फर्जी लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप वॉट्सऐप की कुछ सेटिंग को ऑन कर सकते हैं, जिसके जरिये आप अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं।

- वॉट्सऐप के 2-Step Verification को ऑन रखें। इससे कोई दूसरा व्यक्ति आपके अकाउंट को लॉग-इन नहीं कर पाएगा।
- अगर आपके पास कोई मैसेज आता है जो Forwarded Too Many Times किया गया है तो यह स्कैम मैसेज हो सकता है।
- आपको कभी भी अनजान नंबर से आने वाले वीडियो कॉल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए।

फेसबुक पर हो रहा मार्केट स्कैम

कई मामलों में पता चला है कि फेसबुक पर शेयर मार्केट को लेकर स्कैम चल रहा है। इन स्कैम्स में फ्री ट्रेडिंग के साथ 100 फीसदी का रिटर्न देने का झांसा दिया जाता है। अगर आपके पास भी ऐसे कोई मैसेज या पोस्ट आता है तो आपको इसे जल्द से जल्द रिपोर्ट करना चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ तरीके अपनाने चाहिए।

- आपको मैसेज में दिए गए लिंक पर कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए।
- अगर आप बाजार में निवेश करते हैं तो आपको एक बार सेबी की वेबसाइट पर जाकर फंड या स्टॉक को वेरिफाई कर लेना चाहिए।
- आपको उन ऐप्स को डाउनलोड करने से बचना चाहिए जो गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टो मौजूद नहीं है। दरअसल, इन ऐप्स में मालवेयर होते हैं जो आपके मोबाइल डेटा को चुरा सकते हैं।

इंस्टाग्राम का शॉपिंग स्कैम

शॉपिंग से संबंधित स्कैम इंस्टाग्राम पर काफी चल रहा है। इन स्कैम्स में सस्ते सामान खरीदने का झांसा दिया जाता है। सस्ते सामान या ज्यादा डिस्काउंट के झांसे में आकर स्कैम का शिकार हो जाते हैं। इस तरह के डिस्काउंट से बचने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।

- आप जब भी इंस्टा से शॉपिंग करते हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए कि विज्ञापन या फिर पोस्ट पर Sponserd लिखा हो। अगर उस पर स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा है तो आपको फिर शॉपिंग नहीं करना चाहिए।
- इंस्टाग्राम के पोस्ट के कमेंटबॉक्स में जाकर आपको रिव्यू पढ़ लेना चाहिए। अगर कमेंट हाइड किया गया है तो आपको वह प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदना चाहिए।
- इंस्टाग्राम से शॉपिंग करते समय हमेशा आपको कैश ऑन डिलीवरी के ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहिए।

जरूर करें ये काम

- आपको कभी भी किसी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए।
- अगर आपको कोई मैसेज विश्वसनीय लगता है तब भी आपको एक बार इंटरनेट पर इसे वेरिफाई कर लेना चाहिए।
- अगर आपको कोई स्पैम मैसेज मिलता है तो आप उसे रिपोर्ट करें।
- आपको कभी भी वीडियो के माध्यम से अपनी जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए।

"मौन की चीख": भारत में बलात्कार के संकट का खुलासा

आशीष कुमार

भारत, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और आध्यात्मिक गहराई के लिए प्रसिद्ध है, वहां हर दिन एक गंभीर संकट सामने आता है- एक ऐसा संकट जो हमारी मानवता की मूल भावना को हिला देता है। बलात्कार केवल हिंसा का एक कार्य नहीं है, यह एक व्यक्ति की गरिमा पर गहरा आघात है, समाज के विश्वास के उस नाजुक धागे को तोड़ने का प्रयास है जो हमें जोड़ता है। यह अपराध पीड़ितों को ऐसे घाव देता है जो दिखाई नहीं देते लेकिन जीवन भर उनके साथ रहते हैं। भारत के जीवंत और विविध समाज की सतह के नीचे एक काला और व्यापक साया छिपा हुआ है-एक ऐसा साया जो हमारे समाज की सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा में असफलता को दर्शाता है। अब इस संकट का संगठित और व्यापक समाधान की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है।

भारत में बलात्कार की गहराती छाया

भारत में बलात्कार एक भयावह सच्चाई बन चुका है, जो हर दिन अनगिनत महिलाओं और लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। घर और सड़कें जो सुरक्षा और आराम देने वाले स्थान होने चाहिए-अक्सर इस विनाशकारी अपराध के स्थल बन जाते हैं। आंकड़े चौंकाने वाले हैं: 2021 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार, प्रतिदिन औसतन 86 बलात्कार दर्ज किए जाते हैं, यानी हर घंटे 49 महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं। 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाओं के बाद बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनी और मीडिया कवरेज के बावजूद, ये अपराध लगातार हो रहे हैं, जो इस गंभीर और लगातार बढ़ते हुए संकट को उजागर करता है।

सामाजिक प्रभाव और कानूनी सुधार की आवश्यकता

भारत में बलात्कार केवल एक अपराध नहीं है, यह समाज की गहरी जड़ें जमा चुकी लैंगिक असमानताओं का प्रतीक है। यह समस्या सिर्फ कुछ घटनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज और कानूनी व्यवस्था में मौजूद प्रणालीगत मुद्दा को दर्शाती है। हिंसा का सामान्यीकरण और पीड़ितों को चुप कराकर अपराधियों को बचाने की प्रवृत्ति यह दिखाती है कि हमारा सिस्टम गहराई से त्रुटिपूर्ण है। इस समस्या का समाधान केवल कानूनी सुधारों से नहीं हो सकता, इसके लिए समाज में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है।

इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पहलू पितृसतात्मक सोच को चुनौती देना है, जो हिंसा को बढ़ावा देती है। भारत के कई हिस्सों में, पुरुषों को स्वाभाविक रूप से अधिकार रखने वाला माना जाता है, जबकि महिलाओं को कमजोर समझा जाता है। यह सांस्कृतिक मान्यता न केवल हिंसा को जायज ठहराती है, बल्कि इसे सामान्य भी बना देती है। यह सोच बलात्कार के मामलों को हँडल करने के तरीके में भी दिखाई देती है, जहां अक्सर पीड़ितों के व्यवहार, कपड़ों, या जीवनशैली पर सवाल उठाए जाते हैं, बजाय इसके कि अपराधियों की जवाबदेही तय की जाए।

भारत में बलात्कार: समाज की विफलता और हमारी नैतिक जिम्मेदारी

बलात्कार एक ऐसा घिनौना अपराध है जो न केवल एक महिला के शरीर पर बल्कि उसकी आत्मा पर भी अमिट घाव छोड़ जाता है। यह एक ऐसा अपराध है जो सिर्फ शारीरिक हमला नहीं है, बल्कि इंसानियत पर किया गया सबसे बड़ा विश्वासघात है। फिर भी, जब भी किसी महिला के साथ बलात्कार होता है, तो सबसे पहले उंगलियां उसी पर उठाई जाती हैं। उसे समाज के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, मानो उस पर हुआ अत्याचार उसकी ही गलती हो।

हमेशा लड़कियों पर ही क्यों दोष?

समाज में आज भी यह सवाल अनुत्तरित है कि बलात्कार की घटनाओं में हमेशा लड़कियों को ही दोषी क्यों माना जाता है। क्या उनका पहनावा, उनका बाहर निकलना, या उनकी स्वतंत्रता के अधिकार पर सवाल उठाना जायज है? जब किसी लड़की के साथ कुछ बुरा होता है, तो हमारे समाज में सबसे पहले उसके चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि इस तरह के सवाल उठाकर हम उस पीड़िता को और भी मानसिक यातना देते हैं।

परिवारों में नैतिक शिक्षा का अभाव

हमारे समाज में आज भी कई परिवारों में ₹अच्छे स्पर्श और ब्रे स्पर्श₹ की शिक्षा नहीं दी जाती। माता-पिता, बहन-आई, सभी को यह जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि वे अपने बच्चों को नैतिक मूल्यों के साथ बड़ा करें। बेटों को इस तरह से संस्कारित किया जाए कि वे लड़कियों को उसी सम्मान के साथ देखें जैसा वे अपनी बहन या मां के लिए अपेक्षा करते हैं।

समाज का दोहरा मापदंड

हमारे समाज में यह भी देखा गया है कि जब कोई लड़की अपने विपरीत लिंग के व्यक्ति से मिलती है, तो वह पहले ही शक के साथ मिलती है कि उसकी नीयत सही है या नहीं। यह डर हमारे समाज की उस मानसिकता को दर्शाता है जहाँ महिलाएं कहीं भी सक्षित महसूस नहीं करतीं-न अपने घर में, न अपने कार्यस्थल पर, और न ही समाज में। आज की स्थिति यह है कि लगभग 90% पोक्सो (POCSO) के मामले घर के अंदर ही होते हैं, जो दर्शाता है कि घर जैसी सुरक्षित जगह भी महिलाओं के लिए खतरे से खाली नहीं है।

राम मंदिर का निर्माण और महिलाओं की सुरक्षा

हमारी संस्कृति और धर्म में मंदिरों का निर्माण एक महान कार्य माना जाता है। राम मंदिर का निर्माण भारतीयता और धर्म की प्रतीक है, लेकिन क्या इसका कोई मतलब है जब हमारे समाज की बेटियों, बहनें, और मांएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती? क्या यह विडंबना नहीं है कि हम एक तरफ राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं. और दूसरी तरफ हमारी ही बहन-बेटियों इस देश में सुरक्षित नहीं हैं?

विश्वगुरु बनने का सपना और हकीकत

हम गर्व से कहते हैं कि भारत विश्वगुरु बन रहा है, कि हम एक सुपर पावर बन रहे हैं। लेकिन क्या यह दावा तब तक सच्चा है जब तक हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? जब तक हमारी मांएं, बहनें, और सहकर्मी सुरक्षित नहीं हैं. तब तक हमारा यह सपना सिर्फ एक भ्रम ही है।

समाज के इस दोहरे मापदंड को बदलने की जरूरत है। हमें जिम्मेदारी लेनी होगी, हमे अपने घर के लड़को को इस तरह से पालने की जरूरत है कि वे महिलाओं का सम्मान करें और उन्हें सुरक्षित महसूस कराएं। अटल बिहारी वाजपेई कहते थे की सरकारें आएंगी जायेंगी, कोई हमेशा के लिए नहीं है, कोलकाता का मामला बेहद शर्मनाक है। सरकार को जवाबदेही तय करनी होगी। लेकिन ये भी एक सच है की क्या कोलकाता का मामला पहला मामला है और क्या ये आखरी मामला होगा?

एक बहुत गहरी बात है की सरकार के लिए रेप मामले हो या मर्डर के मामले हो, ये उनके लिए सिर्फ संख्या मात्र होता हैं, ये एक कड़वी हकीकत है। निर्भया का भी केस हुआ था, क्या हुआ उस केस का, जो मुख्य आरोपी था 15 साल का, उसको तो कोई सजा हुई ही नहीं, वो आज भी कही आजादी से घूम रहा है।

हमें यह समझना होगा कि बलात्कार सिर्फ एक अपराध नहीं है, यह हमारे समाज की विफलता है। अगर हम इसे बदलना चाहते हैं, तो हमें अपने बच्चों को सही शिक्षा देनी होगी, हमें उन्हें नैतिक मूल्यों के साथ बड़ा करना होगा।

इस देश को सचमुच महान बनाने के लिए, हमें अपनी महिलाओं को वह सुरक्षा और सम्मान देना होगा जिसकी वे हकदार हैं। तभी हम सच में कह सकते हैं कि हमारा भारत, विश्वगुरु बनने के योग्य है।

सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं का लैंगिक सोच पर प्रभाव

ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों ने समाज में महिलाओं के प्रति सोच को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इस तरह यौन हिंसा के मुद्दों को भी प्रभावित किया है। 'मनुस्मृति' जैसे प्राने हिंदू ग्रंथों ने ऐतिहासिक रूप से पुरुष प्रभुत्व और महिलाओं के अधीनस्थ होने की धारणा को मजबूत किया है। 'मनुस्मृति' में कहा गया है कि महिलाओं को अपने जीवन भर अपने पिता, पति, या पुत्र के नियंत्रण में रहना चाहिए, जिससे पुरुष प्रभुत्व और महिलाओं की अधीनता की सोच को बल मिलता है।

इसी तरह, 'रामायण', जो एक प्रभावशाली हिंदू महाकाव्य है, लैंगिक मान्यताओं को पुष्ट करता है, जैसे कि सीता का ₹अग्नि परीक्षा₹, जो उन्हें रावण दवारा अपहरण के बाद अपनी निष्ठा साबित करने के लिए करना पड़ा। राम भी तो वन में थे, उन्होंने अग्नि परीक्षा क्यूं नहीं दी? इस तरह की कहानियां यह विचार मजबूत करती है कि एक महिला का मूल्य उसकी शुद्धता और आज्ञाकारिता से जुड़ा है, जिससे यह सोच बढ़ती है कि महिलाओं के शरीर पुरुषों के नियंत्रण और समाज के नैतिक मानदंडों के अधीन हैं।

ये सांस्कृतिक कथाएं समाज में सोच और व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालती हैं। ये लैंगिक हिंसा के सामान्यीकरण और महिलाओं के अनुभवों को तुच्छ मानने में योगदान करती हैं। पितृसत्तात्मक मूल्यों का सांस्कृतिक और धार्मिक समर्थन आधुनिक समाज में भी जारी है, जो यौन हिंसा का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के प्रयासों को जटिल बनाता है।

व्यापक सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता

भारत में बलात्कार के संकट का समाधान केवल कानूनी सुधारों से नहीं हो सकता; इसके लिए व्यापक सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है। इस परिवर्तन में उन सांस्कृतिक मान्यताओं और दृष्टिकोणों को चुनौती देना और बदलना शामिल है, जो हिंसा और असमानता को बढ़ावा देते हैं। इसके लिए समाज के सभी स्तरों-सरकारी संस्थानों, नागरिक समाज संगठनों, और व्यक्तिगत नागरिकों से समन्वित प्रयास की आवश्यकता है।

इस परिवर्तन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक कानूनी प्रणाली है। इसके लिए सख्त कानूनों और अधिक प्रभावी न्यायिक प्रक्रिया की आवश्यकता है, ताकि अपराधियों को जिम्मेदार ठहराया जा सके और पीड़ितों को न्याय और सहायता मिल सके। इसमें उन प्रणालीगत मुद्दों का समाधान भी शामिल है. जो कानूनी कार्यवाही में दील और देरी की अनुमति देते हैं, साथ ही यह सुनिश्चित करना कि कानूनों को निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।

इस परिवर्तन का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक मान्यताओं को चुनौती देना है. जो हिंसा को सामान्य बनाते हैं। इसमें लोगों को लैंगिक समानता और महिलाओं की स्वायत्तता के प्रति संवेदनशील बनाने और शिक्षित करने की आवश्यकता है। जन जागरूकता अभियान, शैक्षिक कार्यक्रम, और सामुदायिक पहले समाज की सोच में बदलाव लाने और सम्मान और समानता की संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

इसके अलावा, यौन हिंसा के पीड़ितों का समर्थन इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें परामर्श, चिकित्सा देखभाल, और कानूनी सहायता सहित व्यापक समर्थन सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना शामिल है। इसमें ऐसे स्रक्षित स्थान बनाना भी शामिल है, जहां पीड़ित बिना किसी डर या कलंक के अपनी कहानी साझा कर सकें और मदद मांग सकें।

सामूहिक जिम्मेदारी की भूमिका

बलात्कार और यौन हिंसा के खिलाफ लड़ाई किसी एक व्यक्ति या समूह की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है। यह अर्थपूर्ण परिवर्तन के लिए समाज के सभी क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी की मांग करता है। इसमें अपराधियों को जिम्मेदार ठहराना, पीड़ितों का समर्थन करना, और उन सांस्कृतिक और प्रणालीगत कारकों को चुनौती देना शामिल है जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं।

एक समाज के रूप में, हमें इन गहरी जड़ें जमा चुकी समस्याओं का सामना करना होगा और एक सुरक्षित और अधिक न्यायसंगत दुनिया बनाने के लिए काम करना होगा। इसमें न केवल जवाबदेही और न्याय की मांग शामिल है, बल्कि उन सांस्कृतिक कथाओं और सामाजिक मानदंडों को सक्रिय रूप से बदलने का काम भी शामिल है, जो हिंसा को कायम रखते हैं। ऐसा करके हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं, जहां किसी भी महिला को डर में जीने की जरूरत न हो, जहां उसकी आवाज सुनी जाए, उसके दर्द को समझा जाए, और उसकी गरिमा की प्रखरता से रक्षा की जाए।

तो आइए ने मिल के एक ऐसा भारत का निर्माण किया जाए जहां लड़का हो या लड़की सब इस वतन के नीचे खुली हवा में आजादी से सांस ले सके!!!!!

जय हिन्द, जय संविधान

सीरवी विकास मण्डल नाचाराम मल्लापुर बढेर का वार्षिक सम्मेलन 5 सितंबर को

परिवहन विशेष न्यूज

हैदराबाद नाचाराम मल्लापुर स्थित सीरवी समाज की आस्था का केन्द्र श्री आईमाता मंदिर में समाज बन्धुओं के सानिध्य में विशेष मीटिंग आयोजितकर श्री आईमाताजी के 609 वें अवतरण दिवस व वार्षिक सम्मेलन पर दो दिवसीय कार्यक्रम के तहत भादवा सुदी एकम बुधवार 4 सितंबर रात्रि जागरण व भादवा सुदी बीज (दूज) गुरुवार 5 सितंबर प्रातः वेला में पूजा- अर्चना व महाप्रसादी कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित किया जायेगा।

अध्यक्ष बाबूलाल मुलेवा सचिव तुलसाराम सिन्दड़ा ने संयुक्त रूप से बताया कि हर वर्ष की भांति समाज बन्धुओं के सानिध्य में दो दिवसीय भादवा सुदी बीज महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बुधवार 4 सितंबर प्रातः वेला में श्री आईमाता मंदिर को विशेष फूलों व लाइटिंग से सजाकर माई का विशेष श्रृंगारकर रात्रि 7.11बजे से जागरण आयोजित किया जाएगा। जिसमे आईं मां के चरणों में भजनों के पुष्प अर्पित करेंगे। बाल कलाकार द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम 4 बजे से 7 बजे तक (सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले को अपना नाम दिनांक 1,09,2024सितंबर 2024 तक महिला मण्डल सचिव महोदय को दिरावे गणेश वंदना एवं आईमाता जी पुजा अर्चना श्री आईमाता जी की पूर्ण आरती गुरुवार 5 सितंबर प्रातः 9.15 बजे ज्योत प्रज्वलितकर, पुजा अर्चना, स्वागत, समाज बन्धुओं द्वारा माई के चरणों में श्रीफल भेंटकर परिवार के सुख-समृद्धि की कामना, समाज धर्मसभा का आयोजनकर अध्यक्ष बाबुलाल मुलेवा की अध्यक्षता में मुख्य अतिथियों, पधारे मेहमानों का स्वागत, कोषाध्यक्ष नेमाराम हाम्बड़ द्वारा आय-व्यय का विवरण, पदाधिकारियों का सम्मान एवं अपने विचार व्यक्त करना, सचिव तुलसाराम सिन्दड़ा द्वारा समाज में किये गये विकासशील कार्यो का विवरण, एवं पधारे समाज बन्धुओं व भक्तों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था मंदिर प्रांगण में रहेगी। बीज महोत्सव कार्यक्रम में पदाधिकारी व कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य पधारे भक्तों की सेवार्थ उपस्थित रहेंगे। समाज बन्धुओं से निवेदन है कि बीज महोत्सव पर अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर, नई कार्यकारिणी की शपथ ग्रहण व पुरानी कमिटी को विदाई समारोह 5 सितंबर को सुबह 11 बजे से होगी।समाज बन्धु सपरिवार पधारकर कार्यक्रम का लाभ लेवे। अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन भाषण व धन्यवाद पश्चात कार्यक्रम का समापन्न होगा।

'अस्पतालों को घोषित किया जाए सुरक्षित क्षेत्र', डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर IMA की अहम मांगें; टास्क फोर्स को लिखा पत्र

परिवहन विशेष न्यूज

IMA डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा रोकने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कई अहम मांगें रखी हैं। एसोसिएशन ने स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा को लेकर प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए गठित किए गए टास्क फोर्स को पत्र लिखा है। पत्र में आईएमए ने मांग की है कि अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए।

नईदिल्ली। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने डॉक्टरों और अस्पतालों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए केंद्रीय कानून बनाने और अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। अपनी मांगों को लेकर आईएमए ने राष्ट्रीय टास्क फोर्स (एनटीएफ) को पत्र लिखा है।

हाल ही में कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल डॉक्टर एवं अस्पताल में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर से दुष्कर्म एवं हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनटीएफ का गठन किया था। एनटीएफ को स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रोटोकॉल तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है।

आधे-अधूरे मन से कार्रवाई करती है पुलिस: IMA

आईएमए ने पत्र में लिखा कि केंद्रीय कानून नहीं होने से पुलिस आधे-अधूरे मन से कार्रवाई करती है। इससे घटनाओं की जांच प्रभावित होती है। मजबूत केंद्रीय कानून पूरे देश में हिंसा रोकने में कारगर होगा।

आईएमए ने कहा कि अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने का प्रविधान को प्रस्तावित कानून में भी शामिल किया जा सकता है। सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने से अस्पतालों को सुरक्षा संबंधी अधिकार मिल सकेंगे। आईएमए रेजिडेंट डॉक्टरों की कार्य और जीवन स्थितियों में सुधार की भी मांग की है।

'जल्द फैसले देने की जरूरत', महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर चता जताते हुए न्यायपालिका से ऐसे मामलों में जल्दी फैसले देने की अपील की है। शनिवार को जिला अदालतों के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बच्चों की सुरक्षा को ज्वलंत मुद्दा बताते हुए इसपर गंभीर चिंता जताई। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि न्यायपालिका संविधान की संरक्षक मानी गई है

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर चता जताते हुए न्यायपालिका से ऐसे मामलों में जल्दी फैसले देने की अपील की है। शनिवार को जिला अदालतों के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा को ज्वलंत मुद्दा बताते हुए इसपर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने ऐसे मामलों में त्वरित न्याय की अपील करते हुए कहा कि महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि न्यायपालिका संविधान की संरक्षक मानी गई है और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका ने इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करने का प्रयास किया है। इस मौके पर कानून मंत्री अजुर्न राम मेघवाल ने कहा जिला अदालतें हमारी न्यायपालिका का दर्पण हैं और इन्हीं के माध्यम से आम जनता अपने मन में न्यायपालिका की छवि बनाती है।

सितम्बर महीना अपने जीवन मे दुबारा ना आनेवाला महीना। इस वर्ष सितंबर महीने में चार रविवार चार सोमवार चार मंगलवार चार बुधवार चार गुरुवार चार शुक्रवार और चार शनिवार हैं। इस साल में आनेवाले सितंबर माह को धन वर्षा की तिजोरी कहा जा सकता हैं।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जाति जनगणना का मामला, जनहित याचिका में गिनाए गए फायदे

जाति जनगणना का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इसे लेकर एक जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता की मांग है कि जातिवार जनगणना कराने के निर्देश केंद्र सरकार को दिए जाएं। याचिका में पिछड़े और अन्य हाशिए पर पड़े वर्गों के कल्याण के लिए इसे जरूरी बताया गया है। साथ ही कई और अन्य फायदे भी इसके गिनाए गए हैं।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर केंद्र सरकार को पिछड़े और अन्य हाशिए पर पड़े वर्गों के कल्याण के लिए जातिवार जनगणना कराने का निर्देश देने की मांग की गई है। जनहित याचिका में जनसंख्या के अनुसार कल्याणकारी उपायों को लागू करने के लिए सामाजिक-आर्थिक जातिवार जनगणना की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि सामाजिक-आर्थिक जातिवार जनगणना से वंचित समूहों की पहचान करने, समान संसाधन वितरण सुनिश्चित करने और नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी करने में मदद मिलेगी। साथ ही पिछड़े और अन्य हाशिए पर पड़े वर्गों का सटीक आंकड़ा सामाजिक न्याय और संवैधानिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

प्रजापति समाज दम्माईगुड़ा का भादवी बीज महोत्सव 5 सितंबर को

हैदराबाद: दम्माईगुड़ा स्थित प्रजापति समाज श्री श्रीयादे माता मंदिर प्रांगण में दो दिवसीय बीज महोत्सव कार्यक्रम के तहत भादवा सुदी एकम बुधवार 4 सितम्बर रात्रि जागरण व भादवा सुदी बीज गुरुवार 5 सितम्बर प्रातः वेला में पूजा-अर्चना व महाप्रसादी कार्यक्रम भव्यरुप से आयोजित किया जायेगा।

मीठालाल ब्रंदणा ने बताया कि बुधवार 4 सितम्बर प्रातः वेला में श्री श्रीयादे माता मंदिर को विशेष फूलों व लाइटिंग से सजाकर माई का विशेष श्रंगार कर रात्रि 9 बजे से जागरण रखा गया है। इसमें सोहननाथ प्रजापति,गिरधारीलाल, मोहनलाल प्रजापति एंड पार्टी माई के चरणों में भजनों के पुष्प अर्पित करेंगे।

गुरुवार 17 सितम्बर प्रातः 8.15 बजे ज्योत प्रज्वलितकर पुजा- अर्चना, स्वागत समारोह, समाज बन्धुओं द्वारा माई के चरणों में श्रीफल भेंटकर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना, पधारे समाज बन्धुओं के लिए भोजन- प्रसादी की व्यवस्था मंदिर प्रांगण में 11.30 बजे से रहेगी। पधारे मेहमानों के लिए स्वागत समारोह रखा गया है।। कार्यकारिणी द्वारा आग्रह किया गया है की ज़्यादा से ज़्यादा पधार कर माता जी के दर्शन एवं भजनों एवं भोजन प्रसादी का लाभ लेवे।

क्या सरकार शराबी केलिए स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था करेगी? चंपुआ विधायक सनातन महाकुड़ ने बिधानसभा मे मंत्री से पूछा

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड उडीशा

भुबनेस्वर: क्या सरकार शराबी केलिए स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था करेगी? चंपुआ विधायक सनातन महाकुड़ ने मंत्री से पूछा। शनिवार को सदन में सनातन महाकुड़ ने पूछा कि क्या सरकार के पास राज्य में पूर्ण नशाबंदी के लिए कोई प्रस्ताव है। यदि हाँ, तो यह कब तक प्रभावी होगा? इसके अलावा क्या सरकार राज्य के शराबियों का पंजीकरण कर उन्हें बीमा और स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी? उसने पूछा।इसके जवाब में रोजगार मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा, 'फिलहाल सरकार के पास राज्य में नशाखोरी को पूरी तरह खत्म करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा, राज्य में शराबियों के पंजीकरण और बीमा तथा स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

पारद्वीप बंदर मे घाना के तीन नागरिक अवैध रूप से जहाज में घुस गए और भाग आये

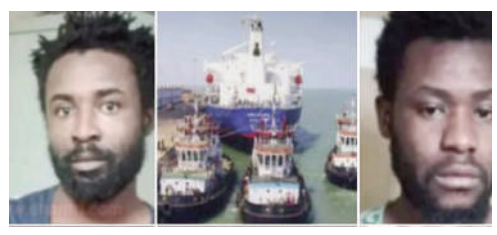

भुबनेश्वर: पारद्वीप बंदर के सीक्यू 1 बर्थ पर रुके चीनी जहाज एमवी ग्रेट शेंग वेन को लेकर शनिवार सुबह से हंगामा मचा हुआ है। घाना के तीन नागरिक अवैध रूप से जहाज में घुस गए और भाग गए। आव्रजन विभाग जांच कर रहा है। जहाज की सुरक्षा सीआईएसएफ के एक जवान द्वारा की जाती है निरीक्षण के बाद जहाज के कैप्टन को नोटिस दिया जाएगा। आव्रजन अधिकारी मानसर्जन दास ने कहा, उस जहाज के नाविक अब भारत के किसी भी बंदरगाह पर नहीं उतर सकते। जहाज में एएमएनएस कंपनी का कोयला आ गया है। जहाज पर कुल 20 नाविक हैं। जिनके कागजात ठीक हैं। अप्रैल में जब जहाज घाना में था तो ये तीन लोग लुकिकी जहाज पर सवार हुए। तब से बोर्ड पर हूँ। जहाज के तुर्की पहुंचने के बाद उक्त 3 नागरिकों को वहां सौंप दिया जाएगा, जहाज के कप्तान ने इमीग्रेशन को इसकी जानकारी दी।

हिमाचल और अवसाद

जनप्रतिनिधि बांट रहे,
हिमाचल को प्रसाद।
फँसा कर्ज के दलदल में,
हुआ उसको अवसाद।
मुफ्त की योजनाओं से,
हुआ उसका बुरा हाल।
दो माह की तनख्वाह देकर,
नेताजी जता रहे एहसान!
इनकी वजह से राज्य का,
खजाना हो गया हैं वीरान।
ऊंट के मुंह में जिरा देकर,
खूब लूट रहें वाह-वाही।
सुना है तनख्वाह रखी है होल्ड,
कहीं रखा हो जैसे कोई गोल्ड।
समझ नहीं आता इन लोगों का,
न जाने आगे क्या है प्लान?
जनता तो हो गई रघुबीरा,
वह तो ख़ाए ककड़ी और खीरा।
नजर आ रहा इनको सेब,
भरनी है अब तो इनको जेब।
ढूंढ रहा है माँ का आंचल,
हमारा प्यारा वो हिमाचल।

संजय एम. तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023